

[ 2023 ] 8 एस. सी. आर. 1026

वाई. बालाजी

वी.

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी।

( अपराधिक अपील सं। 1671-1673 2023 का)

16 मई, 2023

[ कृष्ण मुरारी और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-एस। 3 , 2 ( 1 ) ( यू) धन शोधन का अपराध-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

- तमिलनाडु राज्य में नौकरियों के लिए-नकद घोटाला-चाहे अपराध की आय की पहचान किए बिना या संपत्ति का प्रतिनिधित्व किए बिना

अपराध की आय और एस द्वारा आवश्यक अपराध की आय से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया या गतिविधि। 3 , जो आधार का गठन करता है /

न्यायिक तथ्य, क्या ईडी जांच शुरू कर सकता है और समन जारी कर सकता है-आयोजित: तीनों एफ. आई. आर. एस. ने आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने अवैध रूप से अनुसूची में शामिल अपराध किए थे।

सार्वजनिक परिवहन निगम-यह रिश्तत की राशि है जो अपराध की आय का गठन करती है। धारा 2 (1) (यू)-अवैध संतुष्टि प्राप्त करने वाले लोक सेवक के पास अपराध की आय होती है-केवल पीढ़ी अपराध की आय का एक हिस्सा धन शोधन के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है। 3 6 गतिविधियाँ या प्रक्रियाएँ हैं और उनमें से एक "अधिग्रहण" है-यदि कोई व्यक्ति रिश्तत लेता है, तो वह अपराध की आय प्राप्त करता है, इसलिए, "अधिग्रहण" की गतिविधि होती है-भले ही वह इसे नहीं रखता है, लेकिन इसका "उपयोग" करता है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि "उपयोग" धाराओं में उल्लिखित गतिविधियों में से एक है। 3 - विधेय अपराधों के लिए एफ. आई. आर. एस. तीनों घटकों की पहचान करता है।

एस. 3 , व्यक्ति; प्रक्रिया; और उत्पाद-भ्रष्टाचार का धन अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करता है-भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में, अपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन सियामी जुड़वा बच्चों की तरह-यह तर्क कि ईडी द्वारा जांच बिना किसी मूलभूत/अधिकार क्षेत्र के तथ्यों के शुरू की गई थी, अदालत को धोखा देने के उद्देश्य से है-जहां भी आरोप हैं

भ्रष्टाचार, अपराध की आय का अधिग्रहण है जो स्वयं

मनी लॉन्ड्रिंग के समान-एक बार जब सार्वजनिक रोजगार के मामले में भारी मात्रा में अवैध संतुष्टि के अधिग्रहण से संबंधित जानकारी सार्वजनिक हो जाती है, तो ईडी का कर्तव्य है कि वह एक सूचना रिपोर्ट दर्ज करे।



1026 वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी।

"अधिग्रहण" एक ऐसी गतिविधि है जो धन शोधन के बराबर है और

लोक सेवक द्वारा अर्जित अवैध संतुष्टि "अपराध की आय" का प्रतिनिधित्व करती है, जो इस संबंध में आपराधिक गतिविधि के माध्यम से उत्पन्न होती है।

एक अनुसूचित अपराध-रिश्त की राशि की प्राप्ति धन का एक कार्य है।

धनशोधन-ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने के लिए विजय मदनलाल चौधरी में फैसले के कुछ हिस्सों से निकलने वाले तथ्यों पर सभी तर्क और सभी कानूनी दलीलें पूरी तरह से अस्थिर हैं।

नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से संबंधित आपराधिक कानून के मामले

याचिका में नहीं उठाए गए आधार पर जांच-आयोजित: 'डी', जिनकी मूल शिकायत के कारण अपराध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी

ऐसा प्रतीत होता है कि 2015 के आई. डी. 1 में दोषियों के खिलाफ एक वास्तविक शिकायत थी, लेकिन बाद में वह एक ट्रोजन हॉर्स निकला, जो प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ जांच में तोड़फोड़ करने के लिए तैयार था-तीनों मामलों में नए सिरे से जांच का निर्देश देने का आदेश, वास्तव में आरोपी के लाभ के लिए, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर रखा कि जांच की विश्वसनीयता को कम नहीं किया जाना चाहिए-वास्तव में, आरोपी ने जांच अधिकारी की ओर से शिथिलता के आधार पर नए सिरे से जांच की मांग नहीं की थी, लेकिन यह 'डी' था जिसने जांच अधिकारी की सक्षम सहायता से इसकी मांग की थी-चौकाने वाली बात यह है कि उच्च न्यायालय ने

पहले की जांच को पूरी तरह से समाप्त करते हुए, शुरुआत से ही पुनः जांच शुरू करने का निर्देश दिया-उक्त निर्देश जारी करके, उच्च न्यायालय ने न केवल अब तक की गई जांच को समाप्त करने का निर्देश दिया, बल्कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को भी लगभग मिटा दिया। 2022 मुकदमे के पिछले दौर में पारित

-

विवादित आदेश के साथ समस्या केवल अनुचित नहीं है

भाषा का उपयोग, जैसा कि अभियुक्त द्वारा कम करने की मांग की गई थी और

शिकायतकर्ता, लेकिन कुछ और-धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

सिद्धांत/सिद्धांत-टकटकी निर्णय का सिद्धांत-चाहे

इस तथ्य के आलोक में कि समीक्षा याचिका में नोटिस का आदेश दिया गया है और कुछ कार्यवाहियों में कुछ अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं, यह

इस न्यायालय के लिए इन अपीलों को समीक्षा याचिका के साथ जोड़ना या इन मामलों की सुनवाई को तब तक स्थगित करना आवश्यक है जब तक कि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।

पुनरीक्षण याचिका और अन्य याचिकाओं में प्रस्तुत-आयोजित: समीक्षा याचिका में आदेशित एक नोटिस  
[2023] 8 एस. सी. आर. को नष्ट या कम नहीं करेगा।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विजय मदनलाल चौधरी का अग्रगामी मूल्य-अभियुक्त के वकील का तर्क, यदि स्वीकार किया जाता है, तो न केवल न्यायिक अनुशासन के सिद्धांतों और टकटकी लगाने के निर्णय के सिद्धांत को नष्ट कर देगा, बल्कि देश में सभी लंबित जांच को भी रोक देगा-अभियुक्त को न तो किसी बड़े मामले में निर्देश लेने का अधिकार है और न ही उसे किसी बड़े मामले में निर्देश लेने का अधिकार है।

पीठ या मामले को तब तक स्थगित करने की मांग करना जब तक कि बड़े मुद्दों से जुड़े मामलों में निर्णय नहीं दिया जाता है-उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश से उत्पन्न अपीलों की अनुमति है-उच्च न्यायालय की खंड पीठ का आदेश। 01.09.2022 अलग रखा गया है-ईडी उस चरण से आगे बढ़ने का हकदार है जिस पर उनके हाथ धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002-भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988-आपराधिक कानून द्वारा बंधे थे।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-का इतिहास -

चर्चा की।

आपराधिक व्यवहार नियम, 2019-आर. आर. 231 ( 3 ) , 237 - अपीलार्थी

उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आर के प्रावधानों की अनदेखी की। 231 ( 3 ) और एस भी। 65 बी, साक्ष्य अधिनियम-आयोजित: दोनों दलीलें सारहीन हैं - r.231 मुख्य रूप से अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले अभियुक्त को कुछ अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के अनुदान से संबंधित है-इसमें कहा गया है कि अचिह्नित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नहीं दी जाएंगी-उच्च न्यायालय ने अचिह्नित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के अनुदान का निर्देश देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया है-इसने केवल ईडी को दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी है। r.237 और उसके बाद एक उचित प्रतिलिपि आवेदन दाखिल करना-यह आर के विपरीत नहीं है। 231 ( 3 ) - - इसके अलावा, यह ज्ञात नहीं है कि कैसे एक तर्क S के इर्द-गिर्द घूमता है। 65 बी, साक्ष्य अधिनियम उठाया जाता है - s.65B की चिंता करता है

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता-प्रमाणन के बिना, ईडी उन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का उपयोग साक्ष्य में, पीएमएलए के तहत अभियोजन में करने में सक्षम नहीं हो सकता है-लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर एक नज़र भी नहीं डाल सकते हैं-साक्ष्य अधिनियम, 1872 - s.65B-धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-आपराधिक कानून।

आपराधिक कानून-तमिलनाडु राज्य में नौकरियों के लिए-नकद घोटाले से संबंधित मामले-के रखरखाव पर आपत्ति नव जांच के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा अपील की गई: आपराधिक न्यायशास्त्र पीड़ितों की एक सीमित भूमिका को मान्यता देता है और यह राज्य है जिसे अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने की भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है-ये वाई. बालाजी बनाम।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी।

कानून के सिद्धांतों का विकास तब किया गया जब प्रशासन की प्रक्रिया काफी हद तक अप्रदूषित थी-हालाँकि, जहाँ आपराधिक न्याय प्रणाली

कुछ शिकायतकर्ता और आरोपी एक अपवित्र गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आए हैं, पीड़ितों को ऐसी साझेदारी की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है शिकायतकर्ता के बीच क्या समझौता किया गया था

और अभियुक्त केवल उनके विवाद नहीं हैं, बल्कि न्याय, निष्पक्ष खेल, अच्छी अंतरात्मा और आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत हैं। - आपराधिक मामले की जांच को शिकायतकर्ता और आरोपी द्वारा एक दोस्ताना मैच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा,

मुकदमे के पिछले दौर में लोकस के प्रश्न पर की गई प्रस्तुतियों को उसी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

पहले दौर में कार्यवाही-इसलिए, आरोपी मामला नहीं उठा सकता है।

लोकस का सवाल बार-बार। आपराधिक व्यवहार नियम, 2019-आर. आर. 207 ( 12 ) , 210 - कुछ अपीलार्थियों ने यू/एस द्वारा स्वीकारोक्ति बयानों की प्रतियां दाखिल कीं। 164 ,

सी. आर. पी. सी., अपीलों में पेपर बुक के हिस्से के रूप में-यह तर्क दिया गया था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए इकबालिया बयान हैं

यह पवित्र है और इसकी प्रतियां तीसरे पक्ष को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं-आयोजित: आर से यह स्पष्ट है। 207 ( 12 ) कि जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक एक स्वीकारोक्ति बयान एक गोपनीय दस्तावेज़ है। दाखिल की गई पूर्ण और अंतिम रिपोर्ट-आर। 210 तीसरे पक्ष को निर्णय या आदेश की प्रतियों के अनुदान के लिए न्यायालय में आवेदन करने में सक्षम बनाता है या

न्यायालय की अभिरक्षा में कोई कार्यवाही या दस्तावेज "-इसलिए, ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने कुछ ऐसा दायर किया है जिसके लिए उनकी कभी कोई पहुंच नहीं हो सकती थी-इसके अलावा, कई दस्तावेज कई व्यक्तियों के कहने पर सार्वजनिक क्षेत्र में दिखाई देने लगे थे-इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ है कि अपीलों को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि अपीलकर्ता इस आधार पर दायर किए गए थे

जिन दस्तावेजों तक उनकी कोई पहुंच नहीं हो सकती थी-संहिता

दंड प्रक्रिया, 1973 - s.164।

आपराधिक कानून-तमिलनाडु राज्य में नौकरियों के लिए नकदी घोटाले से संबंधित मामले-राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप-आधार पर घटनाओं की समयरेखा के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि मंत्री को विधान सभा के चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए 08.03.2021 पर मामले में फंसाया गया था, क्योंकि वह सत्ता में पार्टी से दूसरे में चले गए थे-आयोजित: यह कि जांच अधिकारी ने वर्ष 2015 से 08.03.2021 तक पीसी अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करने का विकल्प नहीं चुना, [2023] 8 एस. सी. आर. नहीं हो सकता है।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंत्री को श्रेय दिया जाता है, लेकिन इसे अभियोजन पक्ष की बदनामी के रूप में लिया जाना चाहिए-यदि पद की ढाल ने 2015 से उसकी रक्षा की जब तक कि वह अलग समूह का हिस्सा नहीं बन गया और ढाल को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए हटा दिया गया जब तक कि वह फिर से नहीं बन गया।

अगले शासन में एक मंत्री को राजनीतिक प्रतिशोध का मामला नहीं कहा जा सकता है-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

अभ्यास और प्रक्रिया-पी. एम. एल. ए. मामले में सभी अभियुक्तों के लिए, उनके खिलाफ कोई अपील दायर किए बिना, विवादित आदेश के तहत उन्हें जो मिली थी, उससे अधिक बड़ी राहत देने के लिए तर्क दिए गए थे-आयोजित: कानून में एक सफल पक्ष के लिए (हालांकि दीवानी कार्यवाही में) निर्णय का समर्थन किए बिना डिफेंडी का समर्थन करना संभव है-लेकिन अभियुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो करना चाहा वह निर्णय का समर्थन करना और स्वतंत्र रूप से अपील दायर किए बिना डिफेंडी के विस्तार की मांग करना था-क्योंकि वे

इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाकर एक मौका लिया, वे भी नहीं हो सकता है इसके बाद विवादित आदेश को चुनौती देने में सक्षम, एक बार जब इस न्यायालय द्वारा उस पर अनुमोदन की मुहर लगा दी जाती है और विलय का सिद्धांत लागू हो जाता है-धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002-सिद्धांत/सिद्धांत-विलय का सिद्धांत।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. तीनों मामलों में नए सिरे से जाँच का निर्देश देने वाला आदेश वास्तव में अभियुक्त के लाभ के लिए है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर रखा है कि जाँच की विश्वसनीयता को कम नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, अभियुक्त ने जांच अधिकारी की ओर से शिथिलता के आधार पर नए सिरे से जांच की मांग नहीं की, लेकिन यह 'डी' ही था जिसने जांच अधिकारी की सक्षम सहायता से इसकी मांग की थी। यह तथ्य कि 'डी' की याचिका का उद्देश्य अभियुक्त की मदद करना था, एक और तथ्य से भी स्पष्ट होता है। उसकी मूल शिकायत दिनांक 29.10.2015 जिसके कारण 2015 के अपराध No.441 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, दस व्यक्तियों के खिलाफ थी और उसमें दर्ज अपराध केवल निम्नलिखित थे:

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 406 और 420। इस शिकायत पर,

13.06.2017 पर संहिता की धारा 173 (2) के तहत एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी और इसके परिणामस्वरूप 2017 के CC No.3627 में कैलेंडर मामला दर्ज किया गया था। डी 'इस तथ्य से खुश था कि धारा 173 (2) के तहत दायर रिपोर्ट में पी. सी. अधिनियम के तहत अपराध शामिल नहीं थे। डी 'उस समय इस तथ्य के बारे में परेशान नहीं था कि साक्षात्कार के निशान दर्ज करने के लिए रजिस्टर, फॉरेंसिक वार्ड, बालाजी बनाम को भेजा गया था।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी।

विभाग को प्राप्त नहीं हुआ था। अचानक, वह पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों सहित 2021 के कैलेंडर मामले No.24 के पंजीकरण के लिए धारा 173 (8) के तहत रिपोर्ट दाखिल करने के बाद परेशान हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि उच्च न्यायालय ने पहले की जांच को पूरी तरह से समाप्त करते हुए शुरू से ही पुनः जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इस मामले में एक बचाव अनुग्रह यह है कि 'डी' की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील और आरोपी की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील भी ऐसा नहीं कर सके।

दिनांकित आक्षेपित आदेश के परिचालन भाग का समर्थन करें

31.10.2022 , 2021 के आपराधिक ओ. पी. No.15122 में। उपरोक्त निर्देश जारी करके, उच्च न्यायालय ने न केवल अब तक की गई जांच को समाप्त करने का निर्देश दिया, बल्कि 2022 की आपराधिक अपील Nos.1514-1516 में पारित इस न्यायालय के दिनांकित 08.09.2022 के फैसले को भी लगभग मिटा दिया। इस न्यायालय ने आपराधिक अपील सं. 1 में दिनांकित निर्णय के पैराग्राफ 45 में कहा है। 1514-1516 2022 का "हम यह कहने के लिए विवश हैं कि एक

आपराधिक कानून में नौसिखिया ने अपराधों को इसके तहत नहीं छोड़ा होगा

पी. सी. अधिनियम, अंतिम रिपोर्ट से बाहर। " इस न्यायालय की उक्त राय को नजरअंदाज करते हुए, उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी को नए सिरे से यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि पीसी अधिनियम के तहत अपराध बनाए गए हैं या नहीं। इसलिए, विवादित आदेश के साथ समस्या केवल भाषा के अनुचित उपयोग की नहीं है, जैसा कि अभियुक्त और अभियुक्त के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा कम करने की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता, लेकिन कुछ और। [ पारस 19-22,25] [1054-B-G; 1055-D; 1056-C-D]

2. यह सच है कि आपराधिक न्यायशास्त्र पीड़ितों के लिए एक सीमित भूमिका को मान्यता देता है और यह राज्य है जिसे सौंपा गया है

अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने की भारी जिम्मेदारी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कानून के कुछ सिद्धांत ऐसे समय में विकसित किए गए थे जब आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन की प्रक्रिया ईमानदार और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के हाथों में थी और धारा काफी हद तक अप्रदूषित रही थी। आज की स्थिति अलग है। इस तरह के मामलों में, जहां कुछ शिकायतकर्ता और आरोपी आए हैं

एक साथ मिलकर एक अपवित्र गठबंधन बनाने के लिए, अपराध के पीड़ितों को ऐसी साझेदारी की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। हमने इस मामले में देखा है कि सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, लोक सेवक व्यक्तियों के माध्यम से, व्यक्तियों को अवैध संतुष्टि का भुगतान करते हुए [2023] 8 एस. सी. आर.

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सत्ता में रहते हुए और बाद में अदालत के बाहर समझौते के आधार पर अभियुक्त का समर्थन करते हुए अदालत में आते हुए। शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच केवल उनके विवादों से समझौता नहीं किया गया, बल्कि न्याय, निष्पक्षता, सद्भावना और आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों से समझौता किया गया। वास्तव में, हाथ में मामला वह है जहां केवल रिकॉर्ड के उद्देश्य से दो टीमें हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन किस टीम के लिए खेल रहा है और मैच कहाँ तय किया गया था। वास्तव में, 2022 की आपराधिक अपील Nos.1514 1516 में पी. धरमराज बनाम षण्मुगम में मुकदमे के पिछले दौर में लोकस के सवाल पर बहुत मुखर प्रस्तुतियाँ की गई थीं। लेकिन रखरखाव से संबंधित आपत्तियों को इस न्यायालय द्वारा पहले दौर में उसी कार्यवाही में खारिज कर दिया गया था। इसलिए, अभियुक्त बार-बार लोकस का सवाल नहीं उठा सकता है। [ पारस 33,34] [1060-डी-एच; 1061-ए]

पूर्ण और अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई "। ऊपर निकाला गया नियम 210 तीसरे पक्ष को निर्णय या आदेश या किसी भी कार्यवाही या दस्तावेज़ की प्रतियों के अनुदान के लिए न्यायालय में आवेदन करने में सक्षम बनाता है। न्यायालय की अभिरक्षा "। इसलिए, ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने कुछ ऐसा दायर किया है जिसके लिए उनकी कभी कोई पहुंच नहीं हो सकती थी। कई लोगों के कहने पर कई दस्तावेज सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे हैं। इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ है कि अपीलों को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि अपीलार्थी ऐसे दस्तावेज लेकर आए हैं जिन तक उनकी कोई पहुंच नहीं हो सकती थी। [ पारस 39-41] [1062-D E, G-H;]

ढाल को थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया गया था जब तक कि वह अगले शासन में फिर से मंत्री नहीं बन गए। इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला कहा जा सकता है। [ पैरा 44] [1064-डी-एफ] वाई. बालाजी बनाम।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी।

जनता दल बनाम। एच. एस. चौधरी (1992) 4 एससीसी 305: [ 1992 ] 1 पूरक। एस. सी. आर. 226; सिमरजीत सिंह मान बनाम भारत संघ (1992) 4 एस. सी. सी. 653-लागू नहीं था।

5. चिंताजनक बात यह है कि वी. गणेश कुमार परिवहन निगम के कर्मचारी हैं। दाखिल आरोप-पत्र में उनकी शिकायत पर, जिसे 2020 के सी. सी. No.19 के रूप में फाइल में लिया गया है, इस वी. गणेश कुमार ने प्रत्येक पद के लिए रु. 2,00,000/- से लेकर रु. 4,50,000/- तक की राशि एकत्र की है।

ड्राइवर, कंडक्टर या मैकेनिक, जैसा भी मामला हो। हमें नहीं पता कि परिवहन निगम ने कम से कम उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की है या नहीं। यदि उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, तो निगम को इस वी. गणेश कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, न कि केवल एक पक्ष होने के लिए।

नौकरी-के लिए-नकदी घोटाला, लेकिन निगम का कर्मचारी होने के बावजूद, नए सिरे से जांच के आदेश पर हमला करने के लिए इस अदालत में आने और आरोपी का समर्थन करने के लिए भी। [ पैरा 47] [1065-सी-डी]

6. ईडी ने संहिता की धारा 173 (8) के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही 29.07.2021 पर एक सूचना रिपोर्ट दर्ज की। , 2021 के सी. सी. No.24 में, जिसके तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं

पीसी अधिनियम। यह अंतिम रिपोर्ट 2015 की एफ. आई. आर. No.441 में थी, जिसे मूल रूप से 2017 के सी. सी. No.3627 के रूप में पंजीकृत किया गया था (यह सी. सी. No.24 बन गया)। 2021)। संहिता की धारा 173 (8) के तहत दायर अंतिम रिपोर्ट, जिसमें श्री वी. सेंथिल बालाजी (मंत्री) को अभियुक्त संख्या 1 के रूप में नामित किया गया था और अभियुक्तों के खिलाफ आरोप धारा 406,419,420 के साथ धारा 34 और 120 बी, 465,467,471 और 201 आईपीसी की धारा 7,12,13 (2) के साथ पीसी अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) और आईपीसी की धारा 109 के तहत लगाए गए थे। चूंकि आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 419,420,467 और 471 और पी. सी. अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत अपराधों को आई. पी. सी. की अनुसूची में शामिल किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, ईडी द्वारा 29.07.2021 पर सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [ पैरा 50] [1066-बी-डी] 7. उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा जारी समन को रद्द नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने केवल ईडी को कार्यवाही करने से रोक दिया था

आगे जब तक विधेय अपराधों से संबंधित मामलों पर रोक नहीं हट जाती। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी आरोपी ने उच्च न्यायालय के दिनांक [2023] 8 एस. सी. आर. के आदेश को चुनौती देने वाली कोई अपील नहीं की है।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित आदेश दिनांकित 01.09.2022। इसलिए, कानून में, (i) एक बार जब आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो यह अंतिम रूप ले लेता है। 2021 के आपराधिक संशोधन मामले No.224 को खारिज करने के साथ; (ii) आपराधिक ओ. पी. में नए सिरे से जांच के आदेश के साथ।

इसके खिलाफ कोई अपील दायर किए बिना भी। कानून में एक सफल पक्ष (हालांकि दीवानी कार्यवाही में) के लिए समर्थन करना संभव है। निर्णय का समर्थन किए बिना डिक्री। लेकिन अभियुक्त ने हमारे सामने जो करना चाहा वह निर्णय का समर्थन करना और स्वतंत्र रूप से अपील दायर किए बिना डिक्री के विस्तार की मांग करना था। चूंकि उन्होंने इस तरह का मार्ग अपनाकर एक मौका लिया था, इसलिए वे इसके बाद के विवादित आदेश को चुनौती देने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं, एक बार जब इस न्यायालय द्वारा उस पर अनुमोदन की मुहर लगा दी जाती है और विलय का सिद्धांत लागू हो जाता है। [ पारस 67-70] [1072-A-F]

8.1 यदि धारा 3 के मुख्य भाग को फॉरेंसिक सटीकता के साथ विच्छेदित किया जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि धारा 3 खुद को तीन में संबोधित करती है।

चीजें (जिन्हें हम 3 'पी' कह सकते हैं) अर्थात्, (i) व्यक्ति; (ii) प्रक्रिया या गतिविधि; और (iii) उत्पाद। जहाँ तक धारा 3 द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों का संबंध है, वे हैं, (i) वे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करते हैं; या (ii) वे जो जानबूझकर सहायता करते हैं; या (iii) वे जो जानबूझकर एक पक्ष हैं; या (iv) वे जो वास्तव में शामिल हैं। जहाँ तक प्रक्रिया का संबंध है, यह धारा वाई. बालाजी बनाम की पहचान करती है।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी।

छह अलग-अलग गतिविधियाँ, अर्थात् (i) छिपाना; (ii) अधिकार;

(iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) पेश करना; या (vi) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, जिसमें से कोई भी एक का गठन करने के लिए पर्याप्त है।

अपराध। जहाँ तक उत्पाद का संबंध है, धारा 3 "अपराध की आय" या आय का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति की पहचान करती है।

प्रक्रिया या गतिविधि के उत्पाद के रूप में अपराध। उन तीन चीजों में से जिन्हें धारा 3 संबोधित करती है, अर्थात् (i) व्यक्ति; (ii) प्रक्रिया;

और (iii) उत्पाद, पहले दो के लिए किसी व्याख्या या परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पहलू अर्थात् "उत्पाद", जिसे धारा 3 "अपराध की आय" के रूप में संदर्भित करती है, एक परिभाषा की आवश्यकता है और इसलिए इसे धारा 2 (1) (यू) में परिभाषित किया गया है। [ पारस 96 और 97] [1088-ए-डी]

8.2 तीनों एफ. आई. आर. एस. का आरोप है कि अभियुक्तों ने अवैध रूप से अनुसूची में शामिल अपराध किए थे।

सार्वजनिक परिवहन निगम में कई व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए संतुष्टि। एक मामले में यह आरोप लगाया गया है कि 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की गई थी और दूसरे मामले में 1 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई थी। यह रिश्तत की राशि है जो धारा 2 (1) (यू) के अर्थ के भीतर 'अपराध की आय' का गठन करती है। यह जानना कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है कि अवैध संतुष्टि प्राप्त करने वाले लोक सेवक के पास आय होती है।

अपराध से। यह तर्क कि अपराध की आय का मात्र उत्पादन धन के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है

खंड 3. विधेय अपराधों के लिए प्राथमिकियां धारा 3 के सभी तीन घटकों की पहचान करती हैं, अर्थात्, (i) व्यक्ति; (ii) प्रक्रिया; और (iii) उत्पाद। एफ. आई. आर. में अभियुक्त व्यक्ति वे होते हैं जो प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होते हैं। उन्होंने जो अवैध संतुष्टि ली है, वह अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करती है। (i) पहली बार में इस तरह की अवैध संतुष्टि का अधिग्रहण; (ii) इसे उपयोग में लाने से पहले दागी धन का कब्जा; और (iii) आज इसे बेदाग धन के रूप में पेश करना, प्रक्रिया है या [2023] 8 एस. सी. आर.

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसी गतिविधि जिसमें आरोपी शामिल हुए हों। भ्रष्टाचार का पैसा  
प्रतिनिधित्व करता है। [ पारस 99,100] [1089-ए-एफ]

अपराध की आय का

### 8.3 यह सच है कि कुछ अपराध हैं, जो, हालांकि

अनुसूचित अपराध, अपराध की आय उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, धारा 307 के तहत दंडनीय हत्या का अपराध एक अनुसूचित अपराध है। जब तक कि यह किसी भाड़े के हत्यारे द्वारा लाभ या हत्या के लिए हत्या नहीं है, तब तक यह अपराध की आय उत्पन्न कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। इस प्रकार के अपराधों के संबंध में संभवतः यह तर्क दिया जा सकता है कि केवल अपराध करना ही पर्याप्त नहीं है

लेकिन अपराध की आय का सृजन आवश्यक है। भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन सियामी जुड़वा बच्चों की तरह होता है। भले ही अपराध अमूर्त संपत्ति आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त होती है।

किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में, यह धारा 2 (1) (यू) के तहत अपराध की आय बन जाती है। उपरोक्त को देखते हुए, हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि ईडी द्वारा जांच शुरू की गई थी बिना किसी मूलभूत/अधिकार क्षेत्र के तथ्यों के। हमारे विचार में, एफ. आई. आर. में आरोप (i) अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधि में व्यक्तियों की संलिप्तता; (ii) धारा 3 के अर्थ के भीतर अपराध की आय का सृजन और साथ ही (iii) धनशोधन की ओर इशारा करते हैं। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि जहां भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वहां अपराध की आय का अधिग्रहण होता है जो अपने आप में धन शोधन के समान है। [ पैरा 102,104] [1089-जी-एच; 1090-ए, ई-एफ]

### 8.4 एक बार विशाल के अधिग्रहण से संबंधित जानकारी

एक लोक सेवक द्वारा अर्जित "अपराध की आय" का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक अनुसूचित के संबंध में आपराधिक गतिविधि के माध्यम से उत्पन्न होता है। अपराध। इसलिए, इसके लिए किसी भी अभियान की आवश्यकता नहीं है, किसी के लिए यह कहने के लिए मछली पकड़ने के अभियान की आवश्यकता नहीं है कि रिश्वत की राशि की प्राप्ति धन शोधन का कार्य है। तर्क है कि वहाँ

ई. डी. की ओर से सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था, यह एक स्व-सेवारत तर्क है। यदि ईडी वाई. बालाजी बनाम पर तुरंत एक सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी।

एक विशेष अपराध के लिए एक प्राथमिकी दर्ज करने पर ईडी पर जल्दबाजी में कार्रवाई करने का आरोप लगाया जाएगा। यदि वे किसी विशेष चरण तक नाटक के सामने आने तक प्रतीक्षा करते हैं, तो ईडी पर देरी के दोषी के रूप में हमला किया जाएगा। अभियुक्त को एक लंबी रस्सी देने के लिए ईडी का शुक्रगुजार होना चाहिए।

2016-2021 तक। इसलिए, ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने के लिए विजय मदनलाल चौधरी में फैसले के कुछ हिस्सों से निकलने वाले तथ्यों पर सभी तर्क और सभी कानूनी दलीलें पूरी तरह से अस्थिर हैं। [ पारस 112-114] [1092-B-F]

9. समीक्षा याचिका में आदेशित एक नोटिस समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) है। 2022 का No.219, विजय मदनलाल चौधरी के पूर्ववर्ती मूल्य को नष्ट या कम नहीं करेगा। तर्क

यदि अभियुक्त के लिए विद्वान वकील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह न केवल न्यायिक अनुशासन के सिद्धांतों और टकटकी लगाने के निर्णय के सिद्धांत को नष्ट कर देगा, बल्कि सभी लंबित होने पर रोक भी लगाएगा। देश में जांच। वास्तव में, 25.08.2022 दिनांकित आदेश समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) में पारित किया गया। 2022 का No.219 यह खुलासा करता है कि प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार था कि समीक्षा याचिका में उठाए गए मुद्दों में से कम से कम दो पर विचार करने की आवश्यकता है। हालाँकि आदेश में इसका सटीक वर्णन नहीं किया गया है, वे दो मुद्दे (i) अभियुक्त को ईसीआईआर की एक प्रति प्रदान नहीं करना; और (ii) सबूत के बोझ को उलटना और निर्दोष होने की धारणा से संबंधित हैं।

इस मामले में उत्तरदाता जिन बिंदुओं का प्रचार कर रहे हैं, उनका उन दो मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, अभियुक्त समीक्षा याचिका पर पिग्गीबैक सवारी नहीं कर सकता है। वास्तव में, जैसा कि हमने कहीं और बताया है, अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.09.2022 के आदेश को चुनौती देने वाली कोई अपील नहीं की है। इसलिए, वे उक्त निर्णय के खिलाफ ईडी और अन्य लोगों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करने के लिए बहस करने के लिए अधिकतम हकदार हैं। मान लीजिए कि हम अभियुक्त के विद्वान वकील से सहमत हैं और ईडी द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हैं, फिर भी वे

बचने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश केवल तब तक उनकी रक्षा करता है जब तक कि अन्य कार्यवाही को रोक नहीं दिया जाता है। इसलिए, अभियुक्त को या तो एक बड़ी पीठ के पास संदर्भ की मांग करने या बड़े मुद्दों से जुड़े मामलों में निर्णय दिए जाने तक मामले को स्थगित करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश से उत्पन्न होने वाली अपीलों को अनुमति दी जा सकती है।

23 ] 8 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तदनुसार, इन अपीलों की अनुमति दी जाती है और मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ दिनांक 01.09.2022 को दरकिनार कर दिया गया है। ईडी अब उस चरण से आगे बढ़ने का हकदार होगा जिस पर उनके हाथ विवादित आदेश से बंधे थे। [ पारस 116-119] [1093-A-F]

विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 929-संदर्भित।

10. इस अपील में अपीलार्थी की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम के नियम 232 (3) के प्रावधानों की अनदेखी की है।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। प्रमाणन के बिना, ईडी पीएमएलए के तहत अभियोजन में सबूत में उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए, हम अपील में कोई गुण नहीं पाते हैं। इसलिए, 2022 के आपराधिक ओ. पी. No.5726 में पारित उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.03.2022 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया जाता है। [ पारस 122-124] [1094-C-F]

11. नए सिरे से जाँच के आदेश से उत्पन्न होने वाली अपीलों की अनुमति है। 2021 के आपराधिक ओ. पी. संख्या 15122 में पारित उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.10.2022 के आदेश के उस हिस्से को दरकिनार कर दिया गया है। नई जांच के लिए उक्त मूल याचिका में जारी किए गए निर्देशों को दरकिनार कर दिया गया है। जाँच अधिकारी पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करके सभी मामलों में आगे की जाँच के साथ आगे बढ़ेगा। इस संबंध में जांच अधिकारी की ओर से कोई भी छूट इस न्यायालय के लिए भविष्य में एक विशेष जांच दल नियुक्त करने पर विचार करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। ( (ख)

वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी।

ईडी द्वारा कार्यवाही शुरू करने को खारिज कर दिया जाएगा। ( iii) उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश से उत्पन्न अपील 30.03.2022 बर्खास्त किया जाता है। ( iv) जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने से संबंधित उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.11.2019 और 01.11.2021 के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी जाती है। जाँच अधिकारी आगे की जाँच के साथ आगे बढ़ेगा और दो महीने के भीतर आगे/अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेगा। ( v) 2023 की अवमानना याचिकाएँ और आई. ए. संख्या 26257 खारिज कर दी जाती हैं। [ पैरा 133] [1096-एफ-एच; 1097-ए-सी]

पी. धर्मराज बनाम षण्मुगम 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी

1186 ; धर्मराज बनाम षण्मुगम 2022 (13) स्केल 142; विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक (2013) 5 एससीसी 762: [ 2012 ] 13 एससीआर 1005; अरुण कुमार बनाम भारत संघ (2007) 1 एससीसी 732: [ 2006 ] 6 पूरका एस. सी. आर. 290; बिहटा को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड केन मार्केटिंग

यूनियन लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बिहार ए. आई. आर 1967 एस. सी. 389: [ 1967 ] एससीआर 848; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड (2023) 3 एससीसी315; शौकीन सिंह बनाम देसा

सिंह (1970) 3 एससीसी 881; प्रवर्तन निदेशालय बनाम गगनदीप सिंह 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 514; पार्वती

12.05.2022 ; कांतारू राजीवरु (धर्म का अधिकार, पुनः-9 जे) बनाम भारतीय युवा वकील संघ (2020) 9 एस. सी. सी. 121; असगर अली बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3095; दाउदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 129; बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार (2000) 8 एस. सी. सी. 395: [ 2000 ] 3 पूरका एससीआर 573;

केरल राज्य बनाम। पुथेनकावु एन. एस. एस. करयोगम

( 2001 ) 10 एससीसी 191; पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर (2011) 14 एससीसी 770: [ 2011 ] 15 एससीआर 540; उत्तर रेलवे सहकारी का प्रबंधन [2023] 8 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण,

राजस्थान, जयपुर (1967) 2 एससीआर 476; साक्षी बनाम संघ।

भारत (2004) 5 एस. सी. सी. 518: [ 2004 ] 2 पूरक। एससीआर 723;

दाउदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2005) 2 एस. सी. सी. 673: [ 2004 ] 6 पूरक।

375 ( 378 ) ; रेडक्लिफ बनाम रिबल मोटर सर्विसेज (1939)

ए. सी. 215 (245)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[ 2012 ] 13 एससीआर 1005

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

अप्रयोज्य रखा गया

[ 1992 ] 1 पूरक। एससीआर 226

पै

रा 45

( 1992 ) 4 एस. सी. सी. 653

पै

रा 45

संदर्भित किया गया है

[ 2006 ] 6 पूरक। एससीआर 290

संदर्भित किया गया है

पै

रा 60

[ 1967 ] एससीआर 848

रा 72

पै

संदर्भित किया गया है

( 2023 ) 3 एस. सी. सी. 325

रा 74

पै

संदर्भित किया गया है

( 1970 ) 3 एस. सी. सी. 881

रा 78

पै

संदर्भित किया गया है

[ 2006 ] 6 पूरक। एससीआर 290

संदर्भित किया गया है

रा 78

पै

( 2020 ) 9 एससीसी 121

रा 81

पै

संदर्भित किया गया है

[ 2000 ] 3 पूरक। एससीआर 573

रा 82

पै

संदर्भित किया गया है

( 2001 ) 10 एससीसी 191

रा 82

पै

संदर्भित किया गया है

[ 2011 ] 15 एससीआर 540

पै

रा 82

संदर्भित किया गया है

[ 1967 ] 2 एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

पै

रा 84

[ 2004 ] 2 पूरक। एससीआर 723

पै

रा 85

संदर्भित किया गया है

[ 2004 ] 6 पूरक। एससीआर 1054

पै

रा 85

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक एपी

नं. 1671-1673 2023 तक।

उच्च न्यायालय के 01.09.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मद्रास में डब्ल्यू. पी. सं. में न्यायिक कार्य। 18213 , 18209 और 201 का 12159

वाई. बालाजी बनाम के साथ। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी।

आपराधिक अपील सं। 1674 , 1677 , 1675-1676 , 1678 , 1658-1661 , 1663-1664 , 1662 , 1679 2023 की अवमानना याचिका (सी) Nos.750-751

2023 और आपराधिक अपील सं। 1680 , 1681-1682 , 1665 2023 का

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., अमित आनंद तिवारी, ए. ए. जी., गोपाल शंकरनारायण, सी. ए. सुंदरम,

मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ अग्रवाल, रंजीत कुमार, सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ए. लक्ष्मीनारायणन, बी. करुणाकरन, नर हरि सिंह, बालाजी श्रीनिवासन, सुश्री गौरी पसरीचा, सुश्री आकृति प्रिया, शिवा के., देवशु बहल, रोहन दीवान, लक्ष्मी राव, सुश्री ज्ञानवी दुबे, डी. रघु, के. सतीरेसन, एस. सी. वी. विमल पानी, सुश्री गरिमा जैन, बालाजी श्रीनिवासन, सुश्री मीशा रोहतगी, नकुल मोहता, सुश्री रिया ढींगरा, देवांश श्रीवास्तव, भारत मोंगा, सुश्री रोहिणी, जफर, मुकेश कुमार मारोरिया, प्रशांत भूषण, एन. सुब्रमण्यन, प्रणव सचदेवा, जतिन भारद्वाज, सुश्री नेहा राठी, सुश्री आकृति, राम शंकर एंड कंपनी, सेंथिल जगदीशन, सजल जैन, सुश्री अनसूया चौधरी, रुद्रादित्य खरे, सुश्री मिशा रोहतगी, नकुल

मोहता, सुश्री रिया ढींगरा, भरत मोंगा, सुश्री एलिना मेरिन मैथ्यू, सम्यक जैन, मोहम्मद। ओवैस, आकाश कुमार, गौरव अग्रवाल, मयंक पांडे, आशीष कुमार पांडे, अर्काज कुमार, माधव सिंहल, सुश्री. दीपावली दत्ता, कानू अग्रवाल, विवेक गुप्ता, जोहेब हुसैन, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री देवयानी गुप्ता, शोभित द्विवेदी, सुश्री वैदेही रस्तोगी, कानू अग्रवाल, विवेक गुप्ता, सारद कुमार सिंघानिया, जोहेब हुसैन, सुश्री भव्य पांडे, सुश्री स्नेहा बोटवे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।

2. देरी को माफ कर दिया गया।

3. छुट्टी दे दी गई।

4. दो स्वतंत्र आदेशों से व्यथित, एक मद्रास उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा 31.10.2022 के एक समूह के निपटारे पर पारित किया गया आपराधिक याचिकाएँ और अन्य मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 01.09.2022 पर पारित, प्रवर्तन निदेशालय 1 द्वारा जांच पर रोक लगाते हुए, विभिन्न व्यक्ति जैसे (i) वास्तविक

1 संक्षेप में, "ईडी"

23 ] 8 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिकायतकर्ता; (ii) तीसरे पक्ष; (iii) अभियुक्त; और (iv) ईडी अपीलों के इन समूह के साथ आया है। अपीलों के समूह के अलावा उच्च न्यायालय के उक्त दो आदेशों से उत्पन्न होने वाली दो अपीलें भी हैं, जिनमें से एक में उच्च न्यायालय द्वारा समय बढ़ाने से इनकार करने को चुनौती दी गई है।

जांच पूरी करने के लिए और एक अन्य उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने के लिए, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को विशिष्ट अपराधों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध कुछ दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए सीमित राहत दी गई है। इन अपीलों के अलावा, दो अवमानना याचिकाएं और एक विशेष जांच दल के गठन की मांग करने वाला एक आवेदन भी है।

5. हमने ईडी की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायण, विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण और श्री बालाजी श्रीनिवासन को सुना है।

पक्षकारों (पीड़ितों और एक गैर सरकारी संगठन) के एक समूह की ओर से पेश हुए श्री कपिल सिब्बल, श्री सी. ए. सुंदरम, श्री सिद्धार्थ लूथरा, श्री मुकुल रोहतगी, पक्षकारों (अभियुक्तों) के एक अन्य समूह की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील, सुश्री वी. मोहना और श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, वास्तविक शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील और तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार।

### पृष्ठभूमि तथ्य

6. हाथ में मामलों के समूह की जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं:

( i) नवंबर 2014 में, महानगर परिवहन निगम,

ड्राइवर (746 पद), कंडक्टर (610 पद), जूनियर ट्रेड्समैन (प्रशिक्षु) (261 पद), जूनियर इंजीनियर (प्रशिक्षु) (13 पद) और सहायक इंजीनियर (प्रशिक्षु) (40 पद) जैसे विभिन्न पदों पर नियुक्ति।

( ii) 24.12.2014 पर साक्षात्कार आयोजित होने और चयन सूची प्रकाशित होने के बाद, एक देवासगयम ने 29.10.2015 पर शिकायत दर्ज कराई।

चेन्नई पीएस सी. सी. बी. ने 10 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाया कि उन्होंने एक राशि का भुगतान किया

अपने बेटे के लिए परिवहन निगम में कंडक्टर की नौकरी पाने के लिए पलानी नाम के एक कंडक्टर को रु. हालाँकि, उनके बेटे को नौकरी नहीं मिली और जब उसने पलानी का सामना किया, तो उसे कई लोगों के पास भेजा गया। जब उसने कम से कम पैसे वापस करने की मांग की, तो उसे नहीं मिला। इसलिए, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की जिसे धारा 406,420 के तहत कथित अपराधों के लिए 2015 की एफ. आई. आर. No.441 के रूप में दर्ज किया गया।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ। इस शिकायत में तमिलनाडु सरकार में मंत्री का पद संभालने वाले सहित अब हमारे सामने आने वाले अभियुक्तों को शामिल नहीं किया गया था।

( iii) इसी तरह, एक गोपी ने 07.03.2016 दिनांकित एक याचिका दी

पुलिस आयुक्त ने दावा किया कि उन्होंने कंडक्टर के पद के लिए आवेदन किया था और साक्षात्कार के बाद उनसे एक व्यक्ति ने संपर्क किया था

अशोकन ने मंत्री सेंथिल बालाजी का भाई होने का दावा करते हुए और कार्तिक ने मंत्री सेंथिल बालाजी का बहनोई होने का दावा करते हुए नियुक्ति प्राप्त करने के लिए रिश्वत की मांग की और कहा कि उसने उन व्यक्तियों को रुपये की राशि का भुगतान किया था। यह शिकायत करते हुए कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की, उक्त गोपी ने सी. आर. एल. में एक याचिका दायर की। 2016 की संहिता की धारा 482 के तहत मद्रास में उच्च न्यायालय की फाइल पर ओपी No.7503

दंड प्रक्रिया, 1973 3 ने पुलिस आयुक्त को अपनी शिकायत दर्ज करने और उसी की जांच करने का निर्देश देने की मांग की।

( (iv) उक्त सीआरएल। गोपी द्वारा दायर 2016 के ओ. पी. <आई. डी. 2 का निपटारा उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 20.06.2016 के आदेश द्वारा किया गया था।

उक्त आदेश में, यह दर्ज किया गया कि अतिरिक्त लोक अभियोजक के अनुसार, 81 व्यक्तियों ने पुलिस को इसी तरह की शिकायतें दी थीं और देवासगयम द्वारा दी गई शिकायत 2015 की प्राथमिकी No.441 के रूप में दर्ज की गई थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने गोपी द्वारा दायर उक्त याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रुख अपनाया कि गोपी सहित सभी 81 व्यक्तियों को देवासगयम के कहने पर दर्ज शिकायत में गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।

( V) जब गोपी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के समय अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा यह कहा गया था कि सभी 81 व्यक्तियों सहित देवासगयम द्वारा दायर शिकायत में गोपी को गवाह के रूप में उद्धृत किया जाएगा।

याचिकाकर्ता गोपी ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि देवासगयम को आरोपी पहले ही जीत चुके थे। वास्तव में, यह बताया गया था कि मंत्री को शिकायत में आरोपी के रूप में नहीं देखा गया था

देवासगयम। गोपी द्वारा एक विशिष्ट शिकायत पेश की गई थी कि पुलिस

निचले स्तर के अधिकारियों से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनके बयान को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने सीआरएल में 20.06.2016 दिनांकित एक आदेश पारित किया। गोपी द्वारा दायर 2016 के ओपी No.7503 में कहा गया है कि पुलिस का कर्तव्य है कि वह निचले स्तर के अनुचरों से परे जांच करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैसा कहां गया था। इस तरह के निर्णय के बाद, अदालत ने सहायक पुलिस आयुक्त, केंद्रीय अपराध शाखा (नौकरी रैकेटिंग) को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

2 संक्षेप में "आई. पी. सी".

3 संक्षिप्त "द कोड" [2023] 8 एस. सी. आर. के लिए।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2015 की एफ. आई. आर. No.441 और पुलिस उपायुक्त को इसकी निगरानी करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि देवासगयम के कहने पर पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, इसलिए गोपी द्वारा की गई शिकायत/अभ्यावेदन पर एक और प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

( vi) उच्च न्यायालय द्वारा 20.06.2016 पर पुलिस को निचले स्तर के अधिकारियों से परे जाने और यह पता लगाने के लिए जारी किए गए निर्देश के बावजूद कि कहाँ

गोपी के कुछ खास कहने के बावजूद पैसे का लेन-देन (जनवरी और मार्च, 2015 के दौरान कथित तौर पर मंत्री को दिए गए लगभग 2 करोड़ रुपये से अधिक) समाप्त हो जाता है।

मंत्री के भाई और बहनोई के खिलाफ आरोप लगाते हुए, पुलिस ने कोड की धारा 173 (2) के तहत 13.06.2017 पर अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिसमें देवासगयम द्वारा नामित 10 व्यक्तियों सहित केवल 12 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने पर, मामले को 2015 की एफ. आई. आर. No.441 में 2017 के कैलेंडर केस No.3627 के रूप में गिना गया। अंतिम रिपोर्ट में न तो मंत्री और न ही उनके भाई या बहनोई को आरोपी के रूप में उद्धृत किया गया था। अंतिम रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों पर केवल आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 406,420 और 419 के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे, न कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के किसी भी प्रावधान के तहत। ( vii) एक वी. गणेश कुमार ने तब चेन्नई पीएस सीसीबी के साथ 2017 की एफ. आई. आर. No.298 में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।

मंत्री सेंथिल बालाजी सहित चार व्यक्ति। इसमें कहा गया है कि

शिकायत की कि वह परिवहन विभाग के एक कर्मचारी थे और उनके एक सहयोगी अन्नाराज और उनके दोस्त आर. सहायराजन को प्रभु (मंत्री के एक रिश्तेदार) मंत्री सेंथिल बालाजी के घर ले गए और मंत्री ने उन्हें पैसे लेने का निर्देश दिया। चालक के रूप में नियुक्ति पाने के इच्छुक व्यक्तियों से धन और

चालकों। शिकायत में आगे कहा गया कि मंत्री के निर्देशों के अनुसार, 28.12.2014 से 10.01.2015 तक की अवधि के दौरान कुल Rs.95 लाख की राशि एकत्र की गई थी और हालाँकि यह राशि प्रभु और सहायराजन को दी गई थी, लेकिन पैसे लेकर अलग होने वाले व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया गया था। इसलिए, जिन लोगों ने पैसे दिए, उन्होंने वी. गणेश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उन्हें 09.09.2017 पर शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया। यहां तक कि 2017 की एफ. आई. आर. No.298 के रूप में दर्ज यह शिकायत केवल धारा 406,420 और 506 (1) के तहत अपराधों के लिए थी। मंत्री के खिलाफ 2017 की एफ. आई. आर. No.298 में 07.06.2018 पर एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।

सेंथिल बालाजी और तीन अन्य, केवल दंडनीय अपराधों के लिए

4 संक्षेप में, "पी. सी. अधिनियम"

वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 420 और 506 (1)। यह अंतिम रिपोर्ट विशेष न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और मामले को 2020 के सीसी No.19 के रूप में गिना गया था। विशिष्ट आरोपों के बावजूद, पीसी अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल नहीं किया गया था।

( viii) एक अन्य शिकायत के. अरुलमानी ने 13.08.2018 पर चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई थी।

कि परिवहन निगम में रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले उनके दोस्तों द्वारा एक लाख रुपये की बड़ी राशि एकत्र की गई थी और यह कि वास्तव में जनवरी, 2015 के पहले सप्ताह में मंत्री के आवास पर पी. ए. षण्मुगम को धन का भुगतान किया गया था। यह था।

शिकायत में आगे कहा गया है कि शनमुगम को पैसे देने के बाद,

शिकायतकर्ता ने अशोक कुमार (मंत्री के भाई) और सेंथिल बालाजी (मंत्री) से भी मुलाकात की और मंत्री ने नियुक्ति आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। यह शिकायत चेन्नई सी. सी. बी. पी. एस. द्वारा 2018 की एफ. आई. आर. No.344 के रूप में दर्ज की गई थी, फिर से केवल आई. पी. सी. की धारा 406, 420 और 506 (1) के तहत अपराधों के लिए। हम नहीं जानते कि राज्य पुलिस तीन प्राथमिकियों में से किसी में भी पी. सी. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों को शामिल करने के विचार के खिलाफ क्यों थी। भले ही कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, लेकिन पी. सी. अधिनियम के खिलाफ नहीं हो सकता है।

( ix) जैसा कि अन्य दो शिकायतों के संबंध में हुआ था, 2018 की एफ. आई. आर. No.344 में भी शिकायत की जाँच की गई थी (या नहीं)। जांच की गई) और 12.04.2019 पर एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई। यहां तक कि यह फाइनल

2021 के कैलेंडर मामले No.25 में रिकॉर्ड में ली गई रिपोर्ट में पी. सी. अधिनियम के तहत अपराध शामिल नहीं थे।

( x) इस मोड़ पर, आर. बी. अरुण कुमार नाम का एक व्यक्ति, जो महानगर परिवहन निगम में चालक के रूप में काम कर रहा था और जो

2015 की एफ. आई. आर. No.441 (देवासगयम की शिकायत) से उत्पन्न 2017 की सी. सी. No.3627 में अंतिम रिपोर्ट में गवाह एल. डब्ल्यू. 47 ने सी. आर. एल. में संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया। 2019 का ओ. पी. No.32067, मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए, इस आधार पर कि राज्य पुलिस ने सी. आर. एल. में अपने आदेश दिनांक 20.06.2016 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया है। 2016 का ओ. पी. No.7503 निचले स्तर के अधिकारियों से परे जाने के लिए। अपनी याचिका में, आर. बी. अरुण कुमार ने यह भी बताया कि एक विशाल आरोप का विशिष्ट आरोप

मंत्री सेंथिल बालाजी को 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किए जाने के बाद, जांच एजेंसी द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था और नौकरों के खिलाफ एक नकली आरोप पत्र दायर किया गया था।

इसलिए, दिनांक 27.11.2019 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सहायक [2023] 8 एस. सी. आर. को निर्देश दिया।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुलिस आयुक्त, सी. सी. बी. (जॉब रैकेटिंग) 2017 के सी. सी. No.3627 में आगे की जांच करेंगे और उसी के भीतर पूरा करेंगे।

छह महीने।

( xi) तीन आरोप पत्रों में से किसी में भी पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल नहीं किए जाने से उत्साहित मंत्री सेंथिल बालाजी को 2020 के सी. सी. No.19 में अभियुक्त संख्या 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 2017 वी. गणेश कुमार द्वारा दायर, 2020 के आपराधिक एम. पी. No.7968 में एक याचिका दायर की गई जिसमें 2020 के सी. सी. No.19 में उन्हें आरोपमुक्त करने की मांग की गई। लेकिन विशेष अदालत ने एक दिनांकित आदेश द्वारा आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया

26.08.2020 . मंत्री ने अपनी आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज करने के उक्त आदेश के खिलाफ सी. आर. एल. में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की फाइल पर 2021 का आर. सी. No.224

( xii) लेकिन इस बीच, संहिता की धारा 173 (8) के तहत एक अंतिम (आगे) रिपोर्ट C.C.No में दायर की गई थी। 47 व्यक्तियों के विरुद्ध 2021 का 24

( xiii) परिवहन निगम में विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की पूरी भर्ती के तरीके के बारे में पता चलने पर आगे बढ़ते हुए, जो उम्मीदवार चयन के लिए उपस्थित हुए लेकिन चयनित नहीं हुए, उन्होंने पूरे चयन को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर करना शुरू कर दिया। 2021 के डब्ल्यू. पी. No.9061 में ए. नांबी वेंकटेश द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति को शून्य करने की मांग की गई थी। इसी तरह, पी. धर्मराज और एम. गोविंदरासु ने सहायक अभियंता के पद के संबंध में 2021 के डब्ल्यूपी No.8991 में एक रिट याचिका दायर की।

( xiv) मई, 2021 में राज्य में राजनीतिक माहौल बदल गया। हालांकि प्रमुख अभिनेता बदल गए, लेकिन पटकथा वही रही।

पीड़ितों के लिए और मंत्री का राजनीतिक भाग्य जारी रहा, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली, यहां तक कि नई व्यवस्था में भी।

( xv) इसके बाद, वह व्यक्ति जिसे मंत्री का कथित पी. ए. कहा जाता है, अर्थात् षण्मुगम, जिसे सी. सी. No.25 में अभियुक्त संख्या 3 के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

अरुलमानी द्वारा दर्ज 2018 की एफ़. आई. आर. No.344 से उत्पन्न 2021 की एफ़. आई. आर. ने 2021 की सी. सी. No.25 को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय की फाइल पर 2021 की एफ़. आई. डी. 3> No.13374 में एक याचिका दायर की। उन्होंने उक्त याचिका में दावा किया कि पीड़ितों (अरुलमानी और अन्य और आरोपी) के बीच समझौता हो गया है और इसलिए शिकायत को रद्द किया जा सकता है। मुकदमे के बाद, आर. सहायराजन, जिन पर सी. सी. No.19 में अभियुक्त संख्या 3 था

2020 2021 के Crl.O.P No.13914 में भी एक रद्द करने की याचिका दायर की गई, जिसमें एक Y. बालाजी v शामिल है।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

2020 के सी. सी. No.19 को रद्द करने के लिए संयुक्त समझौता ज्ञापन। इसी तरह, एक वेबरीचेलवन (आरोपी No.10) ने सीआरएल दायर किया। 2021 के ओ. पी. No.6621 2021 के सी. सी. No.24 में कार्यवाही को रद्द करने के लिए।

( xvi) दिनांक 30.07.2021 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने संयुक्त समझौता ज्ञापन के आधार पर 2021 के CC No.25 को रद्द कर दिया। यह आदेश आरोपों की प्रकृति, जिन अपराधों के लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया जाना चाहिए था, और साथ ही स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा पारित पिछले आदेशों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए पारित किया गया था।

( xvii) उच्च न्यायालय द्वारा 2021 के CC No.25 को रद्द करने के आदेश पारित करने से ठीक एक दिन पहले, ईडी ने एक सूचना रिपोर्ट दर्ज की

29.07.2021 ई. सी. आई. आर./एम. डी. एस. जेड. ओ./21/21 में और मंत्री सेंथिल बालाजी को समन जारी किया।

( xviii) इस स्तर पर, देवासगयम जिन्होंने 2015 की एफ. आई. आर. No.441 में पहली शिकायत दर्ज की थी और जिनके मामले में सी. सी. में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।

2017 के No.3627 ने 2021 के Crl.O.P. No.15122 में उच्च न्यायालय की फाइल पर एक बहुत ही अजीब याचिका दायर की जिसमें 2021 के CC No.24 में नए सिरे से जांच की मांग की गई। इस स्तर पर यह याद किया जाना चाहिए कि देवासगयम की शिकायत 2015 की एफ. आई. आर. No.441 दिनांक 29.10.2015 के रूप में दर्ज की गई थी और उसमें एक अंतिम रिपोर्ट 13.06.2017 पर दायर की गई थी जिससे 2017 का कैलेंडर मामला No.3627 सामने आया। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश से गोपी और अन्य लोगों की शिकायत को देवासगयम की जांच के साथ जोड़ दिया गया।

2021 के सी. सी. No.24 में एक अलग कैलेंडर मामला दर्ज करने का मामला। गोपी (सी. आर. एल. में याचिकाकर्ता) द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आरोप लगाए जाने के बाद वास्तव में क्लबिंग हुई। 2016 का ओ. पी. No.7503) इस प्रभाव के लिए कि देवासगयम को जीत लिया गया था। 2015 की एफ. आई. आर. No.441 की जाँच के साथ गोपी की शिकायत को जोड़ने का आदेश देते हुए, उच्च न्यायालय को शायद यह एहसास नहीं था कि यह देवासगयम को पटरी से उतारने में सक्षम बना सकता है (संयोग से वह रेलवे से सेवानिवृत्त हो गए थे और "पटरी से उतरना" शब्द उन्हें सूट करता है) यहाँ तक कि 2021 की सी. सी. No.24 की कार्यवाही भी।

( xix) यह पता लगाना कि पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को केवल एक मामले में शामिल किया गया था और दूसरों में नहीं और इसने सक्षम किया था

उच्च न्यायालय ने एक संयुक्त समझौता ज्ञापन के आधार पर चार कैलेंडर मामलों में से एक को रद्द करने के लिए भी, जो उम्मीदवार भर्ती में असफल रहे और जिन्होंने चयन की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की थीं, उन्होंने अन्य मामलों में रद्द करने की याचिकाओं के साथ-साथ देवासगयम द्वारा नई जांच के लिए दायर याचिकाओं में भी अभियोग दायर किए।



23 ] 8 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( X ) इस स्तर पर, ईडी ने सीसी संख्या में विविध याचिकाएं दायर कीं। 19/20 , 24/21 और एफ. आई. आर., गवाहों के बयान, अंतिम रिपोर्ट, आदि की प्रमाणित प्रतियों की मांग करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष <आई. डी. 1. दिनांक 09.11.2021 के एक आदेश द्वारा, ट्रायल कोर्ट ने एफ. आई. आर. एस., शिकायतों और संहिता की धारा 161 और 164 के तहत बयानों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति का निर्देश दिया। हालांकि, निचली अदालत ने अचिह्नित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने से इनकार कर दिया।

( xxi ) संयुक्त आदेश के आधार पर 2021 के CC No.25 को रद्द करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.07.2021 के आदेश के खिलाफ

समझौता ज्ञापन, एक विशेष अनुमति याचिका पी. धर्मराज द्वारा दायर की गई थी। यह याद किया जा सकता है कि वह असफल उम्मीदवारों में से एक थे और उन्होंने पूरे चयन को रद्द करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। ( xxii ) एंटी-कorrप्शन मूवमेंट नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने भी उच्च न्यायालय के सीसी को रद्द करने के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएँ। दिनांक 30.03.2022 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने ईडी को आपराधिक व्यवहार नियम, 2019 के नियम 237 के तहत निरीक्षण करने और उसके बाद दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति के लिए तीसरे पक्ष के प्रतिलिपि आवेदन करने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि नियम 238 के तहत, ईडी को उद्घरण लेने और उसके बाद विशेष अदालत के समक्ष एक नए तीसरे पक्ष की प्रति आवेदन दायर करने का भी अधिकार था। अदालत। उच्च न्यायालय द्वारा ईडी को अपने दिनांकित 30.03.2022 आदेश में दी गई सीमित राहत को चुनौती देते हुए, एक व्यक्ति जो 2017 के सीसी No.3627 (सीसी No.24/2021) में अभियुक्त संख्या 3 है, एक विशेष अनुमति याचिका के साथ आया है जो मामलों के वर्तमान समूह का हिस्सा है।

( xiv ) इसके बाद, तीन रिट याचिकाएं दायर की गईं, एक मंत्री सेंथिल बालाजी द्वारा और दूसरी शनमुगम द्वारा, जो कथित रूप से उनकी थी। सचिव और अशोक कुमार (मंत्री के भाई) द्वारा तीसरा,

ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी। इन रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, मुख्य रूप से इस आधार पर कि चार कैलेंडर मामलों में से एक को उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त समझौता ज्ञापन के आधार पर दिनांक 2 के आदेश द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया था और अन्य कैलेंडर मामलों में आगे की कार्यवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। 3 5 संक्षिप्त "नियम, 2019" के लिए

वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

कैलेंडर मामले वापस दायर किए जाते हैं लेकिन पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करने का भी निर्देश दिया। ( XXVI) इस न्यायालय के दिनांक 08.09.2022 के निर्णय के बावजूद, उच्च न्यायालय ने दायर याचिका को अनुमति देते हुए दिनांक 31.10.2022 का एक आदेश पारित किया।

देवासगयम द्वारा और एक नए सिरे से जाँच का आदेश दिया गया।

( ) इसलिए, उनके द्वारा जारी समन को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के दिनांक 01.09.2022 के आदेश को चुनौती देते हुए, ईडी सामने आया है।

तीन अपीलों के साथ और वह उम्मीदवार जो चयन में असफल रहा और जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है, एक अपील के साथ आया है।

( XXVIIii) उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.10.2022 के आदेश को चुनौती देना।

नए सिरे से जांच का निर्देश देते हुए ईडी ने एक अपील की है, चयन में असफल रहने वाले दो उम्मीदवार सामने आए हैं दो अलग-अलग अपीलों के साथ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन एक अपील के साथ आया है, वह व्यक्ति जिसने आरोपी के साथ मामले में समझौता किया था।

ईडी द्वारा जारी किया गया। इसी तरह, उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से जांच का निर्देश देने वाले दिनांकित 31.10.2022 आदेश को चुनौती देने वाली हमारी छह अपीलें हैं। ( XXX) हमारे पास दो और अपीलें हैं, जो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं हैं। उनमें से एक अभियुक्त द्वारा आदेश को चुनौती दी गई है

उच्च न्यायालय ने ई. डी. को नियम, 2019 के नियम 237 के तहत निचली अदालत के समक्ष दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी। एक अन्य अपील असफल उम्मीदवार द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए दायर की जाती है जिसमें जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

( ) इस प्रकार, हमारे पास 12 अपीलें हैं, जिनमें से चार में ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने को चुनौती दी गई है, जिनमें से छह में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई है। उनमें से एक ने ईडी को दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती दी और अंतिम आदेश ने जांच पूरी करने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया।

23 ] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( XXXII) अपीलों के अलावा, हमारे पास दो अवमानना याचिकाएं भी हैं

जांच दल पूरे घोटाले की व्यापक जांच करेगा और अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील की नियुक्ति करेगा। यह आवेदन इस आधार पर लिया गया है कि आपराधिक अपील संख्या में इसी तरह की प्रार्थना की गई है। 1514-1516 2022 के इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश में इस उम्मीद में खारिज कर दिया गया था कि राज्य पुलिस निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी। आवेदक/अपीलार्थी के अनुसार, राज्य पुलिस ने इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई आशा को झुठलाया था और इसलिए अब एक विशेष जांच दल का गठन करने का समय आ गया है। 7. चूंकि अपीलों का समूह हाथ में है (जिसमें अवमानना याचिकाएं और विशेष जांच के गठन के लिए आवेदन शामिल नहीं हैं)

दल) उच्च न्यायालय के चार अलग-अलग आदेशों से उत्पन्न होता है, आइए हम इस निर्णय को चार भागों में विभाजित करें, पहला डी नोवो इन्वेस्टिगेशन के आदेश को चुनौती देने से संबंधित है; दूसरा ईडी द्वारा जारी समन को दरकिनार करने वाले आदेश को चुनौती देने से संबंधित है; तीसरा ईडी को ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति देने वाले आदेश से संबंधित है; और चौथा जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने से इनकार करने वाले आदेश से संबंधित है।

भाग-I (नए सिरे से जाँच के आदेश को चुनौती)

8. जैसा कि हमने पहले बताया है, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 31.10.2022 के निर्णय द्वारा नए सिरे से जांच का आदेश दिया है। देवासगयम नामक व्यक्ति, जिसने 29.10.2015 पर शिकायत दर्ज कराने वाला पहला व्यक्ति था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सी. पलानी नामक व्यक्ति इसमें काम कर रहा है।

परिवहन निगम को अपने बेटे के लिए कंडक्टर की नौकरी हासिल करने के लिए रुपये की राशि प्राप्त हुई और उसने और उसके सहयोगियों ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराध किए। यह शिकायत 2015 की एफ. आई. आर. No.441 के रूप में दर्ज की गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि देवासगयम के आरोप अपने बेटे के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए परिवहन निगम के एक कर्मचारी को पैसे के भुगतान से संबंधित थे, पीसी अधिनियम के तहत अपराधों को प्राथमिकी में शामिल नहीं किया गया था।

दिलचस्प बात यह है कि देवासगयम रेलवे के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।

जबकि वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

वह खरीद के लिए अवैध संतुष्टि का भुगतान करने से खुश था अपने बेटे के लिए रोजगार, वह इस बात से नाखुश नहीं था कि पुलिस ने 2015 की एफ. आई. आर. <आई. डी1> में पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल नहीं किया।

9. देवासगयम का यह रवैया 2016 के आपराधिक ओ. पी. No.7503 में गोपी नाम के एक अन्य पीड़ित द्वारा दायर याचिका में देवासगयम के खिलाफ लगाए गए आरोप के लिए जिम्मेदार था, कि देवासगयम को आरोपी ने जीत लिया था।

10. देवासगयम की शिकायत पर, जांच अधिकारी ने 13.06.2017 पर एक अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिसके कारण 2017 के CC No.3627 में एक कैलेंडर मामला दर्ज किया गया। इस अंतिम रिपोर्ट में भी पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल नहीं किया गया था। देवासगयम ने पुलिस से सवाल करने या अदालत का रुख करने की जहमत नहीं उठाई कि पीसी अधिनियम के तहत अपराधों को क्यों शामिल नहीं किया गया।

11. लेकिन सौभाग्य से, गोपी द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, एक और कैलेंडर मामला दर्ज किया गया

2021 के सी. सी. No.24 में, संहिता की धारा 173 (8) के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत एक और रिपोर्ट पर। 2021 के इस सी. सी. No.24 में, मंत्री और उनके सहयोगियों को अभियुक्त के रूप में शामिल किया गया था और इसके तहत अपराध पी. सी. अधिनियम शामिल किए गए थे।

12. संहिता की धारा 173 (8) के तहत यह आगे की रिपोर्ट जो 2021 के सी. सी. No.24 के पंजीकरण में समाप्त हुई, पर दायर की गई थी। 08.03.2021 .

13. मंत्री और उनके सहयोगियों का नाम शामिल करना

धारा 173 (8) के तहत प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट और पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करने से ऐसा लगता है कि देवासगयम ने खुद मंत्री से ज्यादा परेशान किया है। इसलिए, देवासगयम ने एक याचिका दायर की

2021 के आपराधिक ओ. पी. No.15122 में 2021 के सी. सी. No.24 में जांच अधिकारी को नए सिरे से जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

14. जिन आधारों पर देवासगयम ने नए सिरे से मांग की

जाँच बहुत अजीब थी। नव जांच की मांग करने वाली अपनी याचिका में, देवासगयम ने कहा कि हालांकि उनकी विशिष्ट शिकायत एक भास्कर और नौ अन्य के खिलाफ थी, लेकिन धारा 173 (8) के तहत दायर अंतिम रिपोर्ट में अन्य व्यक्ति शामिल थे, जिनका देवासगयम के अनुसार मामले से कोई संबंध नहीं था। देवासगयम ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि भास्कर और केशवन, जिनके खिलाफ उन्होंने एक विशिष्ट शिकायत की थी, को आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है। वास्तव में, गोपी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में लगाया गया आरोप कि [2023] 8 एस. सी. आर.

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देवासगयम को आरोपी ने जीत लिया था, उसके बिना नहीं था सार, जैसा कि देवासगयम द्वारा 2021 की अपनी याचिका क्रिमिनल ओ. पी. No.15122 में किए गए कुछ कथनों से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, नई जांच की मांग करने वाली अपनी याचिका के पैराग्राफ 7 में उन्होंने इस प्रकार कहा:

" यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने भास्कर और केशवन के खिलाफ एक विशिष्ट शिकायत की है। भास्कर और केशवन नाम के काल्पनिक व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था

नंबर 1 और 2। ..... 99

15. यह ज्ञात नहीं है कि क्या देवासगयम उन व्यक्तियों का उल्लेख कर रहा था जिनके खिलाफ उसने एक विशिष्ट शिकायत काल्पनिक व्यक्तियों के रूप में की थी या क्या वह मंत्री और अंतिम रिपोर्ट में आरोपी के रूप में नामित व्यक्ति, जिसे कथित रूप से उसका सचिव कहा गया था, को काल्पनिक व्यक्तियों के रूप में बुला रहा था।

पैराग्राफ 10 में कहा गया है कि धारा 173 (8) के तहत अंतिम रिपोर्ट उसे नोटिस जारी किए बिना दायर की गई थी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट में निहित आरोप उसके अपने मामले के तथ्यों के लिए अप्रासंगिक हैं। देवासगयम की याचिका के पैराग्राफ 28 से 30 जाँच से पता चलता है कि वह मुख्य दोषियों के मामले की पैरवी करने की हद तक गया था। ये परिच्छेद इस प्रकार हैं:

" 28. अंतिम रिपोर्ट को समाप्त करने में घोर उल्लंघन और अनियमितता, उपरोक्त सभी के साथ यह कहना उचित है कि अंतिम रिपोर्ट किसी के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए वारंट नहीं करती है और

दर्ज किया गया अपराध प्रेरित है। अदालती कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अभियोजन।

29. अंतिम रिपोर्ट में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, लेकिन वे उनके चंगुल से बच सकते हैं।

कानून से।

30.

वर्तमान आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से भाग लिया जाता है और/या कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।

17. ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि देवासगयम को वाई. बालाजी बनाम के निचले भाग में दोषियों के खिलाफ एक वास्तविक शिकायत थी।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

लेकिन बाद में वह एक ट्रोजन हॉर्स निकला, जो प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ जांच में तोड़फोड़ करने के लिए तैयार था। यह तथ्य आपराधिक ओ. पी. में याचिका के पैराग्राफ 31 में उनकी दलीलों से अधिक स्पष्ट होता है।

2021 का No.15122। पैराग्राफ 31 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

" 31. .... जहाँ तलाशी और गिरफ्तारी पर एकत्र की गई अवैध सामग्री के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है जो प्रति

यह अवैध है और न केवल एक दोषसिद्धि और सजा को दूषित करता है

ऐसी सामग्री के आधार पर, लेकिन स्वयं मुकदमे के आधार पर, कार्यवाही

इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह दुरुपयोग के बराबर नहीं हो सकता है

न्यायालय की प्रक्रिया; ऐसे मामले में रद्द नहीं करना कार्यवाही प्रक्रिया के दुरुपयोग को कायम रखेगी

न्यायालय के परिणामस्वरूप बड़ी कठिनाई और अन्याय हुआ

अभियुक्त। हमारी राय में, धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग  
<आई. डी.  
1.....।

वास्तव में न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करता है।

18. देवासगयम के उपरोक्त कथन से यह देखा जाता है कि वह

वस्तुतः अभियुक्त के मामले की पैरवी कर रहा था और नए सिरे से जाँच की मांग कर रहा था। लेकिन अफसोस की बात है कि केवल देवासगयम को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। अभियोजन पक्ष में उनका एक मूक भागीदार था जिसे हम अब देखेंगे। यदि देवासगयम ने वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए कई मील की छलांग लगाई, तो ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय एक ऐसे बिंदु पर नए सिरे से जांच का आदेश देकर एक कदम आगे बढ़ गया है जिसका प्रचार नहीं किया गया है।

देवासगयम द्वारा दायर याचिका। वास्तव में, उच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.2022 के विवादित आदेश के मुख्य पैराग्राफ 21 में, उच्च न्यायालय ने इन लोगों की ओर से आगे की गई दलीलों पर विस्तार से चर्चा की है।

देवासगयम नए सिरे से जाँच के लिए अपनी याचिका के समर्थन में। ये दलीलें 2021 के आपराधिक ओ. पी. संख्या 15122 में उनकी याचिका में निहित कथनों के अनुरूप थीं। 19. यद्यपि मूल याचिका

और विवादित आदेश के पैराग्राफ 21 में दर्ज दलीलें एक विशेष आधार को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, लेकिन विवादित आदेश का परिचालन भाग याचिका में नहीं उठाए गए आधार पर नए सिरे से जांच की अनुमति देता है। विवादित आदेश के पैराग्राफ 55 में, उच्च न्यायालय द्वारा यह दर्ज किया गया था कि जांच अधिकारी द्वारा

दायर हलफनामे के अनुसार, जांच एजेंसी ने साक्षात्कार के निशान दर्ज करने के लिए उपयोग किए गए रजिस्टर को जब्त कर लिया था और हेरफेर का पता लगाने के लिए उसे विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक विभाग को भेज दिया था और कोड की धारा 173 (8) के तहत अंतिम रिपोर्ट फॉरेंसिक विभाग की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही दायर कर दी गई थी। यह इस विवाद [2023] 8 एस. सी. आर. पर है।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच अधिकारी। 20. यह तथ्य कि देवासगयम की याचिका का उद्देश्य अभियुक्त की मदद करना था, एक और तथ्य से भी स्पष्ट होता है। उनकी मूल शिकायत

दिनांक 29.10.2015 जिसके कारण 2015 के अपराध No.441 में दस व्यक्तियों और उसमें दर्ज अपराधों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी

केवल आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 406 और 420 के तहत थे। इस शिकायत पर, 13.06.2017 पर संहिता की धारा 173 (2) के तहत एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी और इसके परिणामस्वरूप 2017 के CC No.3627 में कैलेंडर मामला दर्ज किया गया था। देवासगयम इस तथ्य से खुश थे कि धारा 173 (2) के तहत दायर रिपोर्ट में पी. सी. अधिनियम के तहत अपराध शामिल नहीं थे। देवासगयम उस समय इस बात से परेशान नहीं थे कि फोरेंसिक विभाग को भेजे गए साक्षात्कार के निशान दर्ज करने के लिए रजिस्टर प्राप्त नहीं हुआ था। अचानक, वह पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों सहित 2021 के कैलेंडर मामले No.24 के पंजीकरण के लिए धारा 173 (8) के तहत रिपोर्ट दाखिल करने के बाद परेशान हो गया।

21. चौंकाने वाली बात यह है कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया

पहले की जांच को पूरी तरह से समाप्त करते हुए, शुरू से ही पुनः जांच शुरू की जाएगी। इस मामले में एक बचाव अनुग्रह यह है कि यहां तक कि देवासगयम की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील और आरोपी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील भी 2021 के आपराधिक ओ. पी. No.15122 में दिनांकित 31.10.2022 के विवादित आदेश के परिचालन भाग का समर्थन नहीं कर सके। आक्षेपित के अनुच्छेद 79 से 81

31.10.2022 दिनांकित आदेश को निकालने की आवश्यकता है। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" 79. इसलिए, मेरा विचार है कि पुनः जांच होनी चाहिए

शुरुआत में पहले की जांच को समाप्त करना शुरू किया

पूर्णतः और उपरोक्त आपराधिक मामलों में नए साक्ष्य और सामग्री एकत्र करना। इसलिए, मैंने Crl.O.P.No को अनुमति दी। 2021 का 15122 नए सिरे से जांच के लिए 2021 के C.C.No.24 में

2021 का C.C.No.19।

वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

80. इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि जांच पहले के संदर्भ के बिना व्यापक रूप से की जानी चाहिए।

अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाया गया। विशेष न्यायालय जिसके समक्ष C.C.No है। यदि राज्य/जाँच अधिकारी की ओर से कोई अनिच्छा है तो 2020 का 19 और 2021 का <ID2 धारा 216 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 81. इसके अलावा, जांच पूरी होने पर, यदि जांच एजेंसी आरोपी के खिलाफ अपराध के संज्ञान के लिए मामला बनाती है, तो विधेय अपराध की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को प्रासंगिक सामग्री/दस्तावेज प्रदान करेगी ताकि वह इसके बाद P.M.L.A अधिनियम के तहत अपनी जांच शुरू करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सके।

22. उपरोक्त निर्देश जारी करके, उच्च न्यायालय ने न केवल अब तक की गई जांच को समाप्त करने का निर्देश दिया, बल्कि लगभग इस न्यायालय के दिनांकित 08.09.2022 के फैसले को भी मिटा दिया।

आपराधिक अपील सं. में पारित। 1514-1516 2022 तक। न्यायिक अनुशासन की जय हो!

23. श्री कपिल सिब्बल, अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ वकील।

देवासगयम ने हमारे सामने तर्क दिया कि विवादित आदेश के पैराग्राफ 79 से 81 में परिलक्षित समस्या भाषा की है न कि कानून की। उनके अनुसार, "मिटा दिया गया" अभिव्यक्ति का उपयोग संदर्भ से बाहर किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा जिसे हटाने की मांग की गई थी, वह केवल पहले से एकत्र की गई सामग्री के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा किए गए निष्कर्ष थे। दूसरे शब्दों में, उनका तर्क था कि अब तक की गई जांच और अब तक एकत्र की गई सामग्री को कभी भी कूड़ेदान में नहीं डाला जा सकता है, लेकिन उन सामग्रियों के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा किए गए निष्कर्ष

केवल मिटाने की आवश्यकता है। 24. यह सच है कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। यह भी सच है कि कुछ भत्ते (या 0 से 90 प्रतिशत तक की छूट) हो सकते हैं।

कभी-कभी कुछ ढीले भावों के उपयोग के लिए दिया जाता है। लेकिन आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 79 से 81 में उपयोग की गई अभिव्यक्तियाँ केवल भाषा या कानून में कमी को नहीं दर्शाती हैं, बल्कि कुछ और दर्शाती हैं।

अधिकांश जैसा कि श्री गोपाल शंकरनारायणन ने ठीक ही कहा है, विद्वान [2023] 8 एस. सी. आर.

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. उपरोक्त शब्दों और वाक्यांशों के उपयोग के अलावा, जो हमारी राय में न केवल कानून में एक छोटी सी खामी खोलते हैं, बल्कि आकाशगंगा में एक विशाल ब्लैक होल खोलते हैं, उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 80 में एक और निर्देश जारी किया। यह निर्देश जांच एजेंसी को यह पता लगाने के लिए है कि पीसी अधिनियम के तहत अपराध हैं या नहीं। अभियुक्त के खिलाफ बनाया जाता है या नहीं। इस तरह का निर्देश इस बात पर गौर करता है कि इस न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या में 08.09.2022 दिनांकित निर्णय के पैराग्राफ 45 में क्या कहा है। 1514-1516 2022 तक। इस अदालत ने कहा है, "हम यह कहने के लिए विवश हैं कि आपराधिक कानून में एक नौसिखिया भी पीसी अधिनियम के तहत अपराधों को अंतिम रिपोर्ट से बाहर नहीं छोड़ता।" इस न्यायालय की उक्त राय को नजरअंदाज करते हुए, उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी को नए सिरे से यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि पीसी अधिनियम के तहत अपराध बनाए गए हैं या नहीं। इसलिए, विवादित आदेश के साथ समस्या केवल भाषा के अनुचित उपयोग की नहीं है, जैसा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा कम करने की मांग की गई है, बल्कि कुछ और है।

26. यहां तक कि विवादित आदेश का समर्थन करते हुए, आरोपी के विद्वान वरिष्ठ वकील और देवासगयम के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमसे विवादित आदेश के पैराग्राफ 79 से 81 को पढ़ने और उसके इरादे के अनुसार चलने का अनुरोध किया। लेकिन यह कहना करने की तुलना में आसान है क्योंकि हमारे पास इस न्यायालय के कानूनों को पढ़ने के उदाहरण हैं लेकिन कभी भी एक भी नहीं।

एक निर्णय पढ़ें। अभियुक्त के वकील और देवासगयम के वकील द्वारा भी इस प्रकार लिए गए रुख को देखते हुए, नए सिरे से जांच से संबंधित कानून से निपटना सख्ती से आवश्यक नहीं हो सकता है। फिर भी हम विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक के फैसले का एक उपयोगी संदर्भ देंगे।

27. विनय त्यागी (ऊपर) कुछ विशिष्ट तथ्यों से उत्पन्न हुए। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत दो व्यक्ति,

1908 , आई. पी. सी. के कुछ प्रावधान और शस्त्र अधिनियम की धारा 25। अभियुक्तों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस आधार पर जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की कि वे मुखबिर के रूप में काम कर रहे थे

6 ( 2013 ) 5 एस. सी. सी. 762 वाई. बालाजी बनाम।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [बी. रामसुब्रमणियन, जे.]

खुफिया एजेंसियों के लिए और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। हालांकि उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार किया, लेकिन कोई रोक नहीं लगाई गई। इसलिए, दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ आगे बढ़ा

जाँच की और आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर सीबीआई को जांच करने और अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तदनुसार, सी. बी. आई. ने एक जांच शुरू की और एक रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच से विश्वास पैदा नहीं हुआ और आगे की जांच की आवश्यकता थी। इसके बाद, सी. बी. आई. ने एक समापन रिपोर्ट दाखिल की। उसी के आधार पर, आरोपी ने आरोपमुक्त करने की मांग की। चूंकि आरोपमुक्त करने का आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उच्च न्यायालय ने मामले को वापस सत्र न्यायालय में भेज दिया। यह रिमांड के उक्त आदेश है जिसे जांच अधिकारी ने इस अदालत के समक्ष चुनौती दी थी। इस न्यायालय ने दो प्रश्न तैयार किए जिनके लिए

विनय त्यागी में विचार। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" प्रश्न 1

जहाँ न्यायालय के आदेशों को आगे बढ़ाने के लिए एक ही या अलग-अलग जांच एजेंसियों द्वारा दो रिपोर्ट होती हैं? यदि ऐसा है तो किस लिए? प्रभाव?

प्रश्न 2

1.2 . क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में "सी. बी. आई".) को "नए सिरे से"/"पुनः जांच" करने का अधिकार है, जब धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है।

कोड? "

28. प्रथम प्रश्न पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने बताया कि जाँच तीन प्रकार की हो सकती है, अर्थात् (i) प्रारंभिक जाँच; (ii) आगे की जाँच; और (iii) नई या नई या पुनः जाँच। पैराग्राफ 21 में "प्रारंभिक जाँच" के अर्थ और पैराग्राफ 22 में "आगे की जाँच" के अर्थ की खोज करने के बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 23 में दर्ज किया कि एक नई जाँच/पुनः जाँच/डी नोवो जाँच क्या है और किन परिस्थितियों में इसका आदेश दिया जा सकता है। निर्णय का अनुच्छेद 23 इस प्रकार है:

" 23. हालांकि, एक "नई जांच" के मामले में,

" पुनः जाँच "या" नए सिरे से जाँच "अदालत का एक निश्चित आदेश होना चाहिए। अदालत के आदेश में स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि क्या पिछली जांच, कारणों से [2023] 8 एस. सी. आर.

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभिलिखित किया जाना, उस पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। न तो जांच एजेंसी और न ही मजिस्ट्रेट के पास "नई जांच" का आदेश देने या संचालन करने की कोई शक्ति है। यह मुख्य रूप से इस कारण से है कि यह संहिता की योजना का विरोध करेगा। यह आवश्यक है कि "नए सिरे से"/"नए सिरे से" जांच का आदेश भी पारित किया जाए पहले से की गई जांच के भाग्य के बारे में उच्च न्यायपालिका को हमेशा एक विशिष्ट निर्देश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जिन मामलों में इस तरह का निर्देश जारी किया जा सकता है, वे बहुत कम हैं।

बीच में। यह हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र के एक मौलिक सिद्धांत पर आधारित है जो यह है कि एक संदिग्ध या आरोपी का न्यायसंगत और निष्पक्ष जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार है। यह सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में निहित संवैधानिक जनादेश से निकलता है। जहां जांच अनुचित, दागी, दुर्भावनापूर्ण और गलत तरीके से की जाती है, अदालतें इस तरह की जांच को दरकिनार कर देंगी और नए सिरे से या नए सिरे से जांच का निर्देश देंगी और यदि आवश्यक हो, तो किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा भी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह व्यापक प्रचुरता की एक शक्ति है और इसलिए, इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। दुर्लभतम मामलों का सिद्धांत ऐसे मामलों पर पूरी तरह से लागू होगा। जब तक कि जांच की अनुचितता ऐसी नहीं है कि यह अदालत की न्यायिक अंतरात्मा को चोट पहुंचाती है, तब तक अदालत को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए ताकि जांच को रद्द किया जा सके और

एक "नई जांच" का निर्देश देना।

29. पैराग्राफ 43 और 45 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नए सिरे से जांच का आदेश देने की शक्ति केवल उच्च न्यायालयों के पास निहित है और

इसका प्रयोग असाधारण मामलों में संयम से किया जाना चाहिए। पैराग्राफ में

46 , इस न्यायालय ने कहा कि नए सिरे से जांच का आदेश देते समय, उच्च न्यायालय के लिए दो विकल्प खुले हैं, अर्थात् (i) पहले से तैयार की गई रिपोर्ट या अब तक की गई जांच को निर्देश देना, मामले के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाना; या (ii) पहले से तैयार की गई रिपोर्ट या रिकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए अब तक की गई जांच को निर्देश देना। अगर

30. इन अपीलों में आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने चार अलग-अलग अभिव्यक्तियों और वाक्यांशों का उपयोग करके संकेत दिया है कि अब तक की गई जांच अभिलेख का हिस्सा नहीं होगी।

लेकिन वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

यहां तक कि देवासगयम के विद्वान वरिष्ठ वकील और अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के परिचालन भाग को इस तरह से समझने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा है तो उन सभी वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों को हटा दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें हटा दिया जाता है, तो जीवन विवादित क्रम से बाहर निकल जाता है, जो हमारी राय में, यह समृद्ध रूप से योग्य है।

31. भाग-1 में अपनी चर्चा को समाप्त करने से पहले, यह आवश्यक हो सकता है

इन अपीलों की स्थिरता के लिए अभियुक्त की ओर से उठाई गई कुछ प्रारंभिक आपत्तियों से निपटने के लिए। पक्षकारों की स्थिति के आधार पर रखरखाव का सवाल उठाया जाता है। इसलिए, उन पक्षों की स्थिति का जायजा लेना आवश्यक है जिन्होंने नए सिरे से जांच के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। आसान के लिए

मूल्यांकन, उन पक्षों की स्थिति जो नए सिरे से जांच के आदेश से उत्पन्न अपीलों में अपीलकर्ता हैं और वे कौन हैं, इसका एक संक्षिप्त संकेत एक सारणीबद्ध कॉलम में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

वह कौन है और वह कैसा है, इसका

संक्षिप्त विवरण

अपीलार्थी के नाम से उत्पन्न सिविल अपीलें

विशेष अवकाश याचिकाएँ और

नोवो के आदेश से व्यथित

डायरी संख्याएँ

जाँच

एसएलपी (सीआरएल) नं. 1207-1208 में से

निदेशक,

छाया

पड़

ईडी दुखी है क्योंकि उस पर कोई  
जाती है।

विधेय अपराध की जाँच, है

प्रवर्तन

2023

धन के अपराध की जाँच

लॉन्ड्रिंग।

वाई. बालाजी

वे इस पद के इच्छुक उम्मीदवारों में

से एक थे

एसएलपी (सीआरएल) 2022 का No.11396

रिट याचिका दायर  
निदेशक, सतर्कता को निर्देश देने की मांग

बढ़ेगी

द  
याचिका लंबित है।

एसएलपी (सीआरएल) 2022 का No.11397

एस. पृथ्वीराजन

उम्मीदवारों में से एक हैं।

उसके निशान थे

लिप्त  
भ्रष्टाचार से लड़ने में रुचि रखने वाला एक गैर सरकारी संगठन।

एसएलपी (सीआरएल) 2023 का D.No.961

भ्रष्टाचार विरोधी

आंदोलन

एसएलपी (सीआरएल) डी. नहीं। 10217 2023 का

No.298 में शिकायतकर्ता छलाह।

वी. गणेश कुमार

खिलाफ दर्ज

सहायराजन;

तहत अपराधों के लिए

2021 के WP No.24275 में  
की गई

और भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई आगे

2020 के सीसी No.19 में जांच।  
रिट

वह जूनियर के पद के इच्छुक

इंजीनियर। वह दावा करता है कि

ऐसे उम्मीदवार जो भ्रष्ट आचरण में  
थे।

ओ दिनांकित एफ. आई. आर.

09.09.2017 , (i) मंत्री के

सेथिल बालाजी; (ii) प्रभु; (iii)

और (iv) अन्नराज, धाराओं के

406 , 420 और 506 (1)

आई. पी. सी.। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने

अभियुक्त के साथ समझौता किया

और उनकी याचिका में उनका  
किया

समर्थन

एफ. आई. आर. को रद्द करना। अब वह दुखी है

स्पष्ट रूप से नए सिरे से जांच का

आदेश

कारणों से।

एसएलपी (सीआरएल) डी. नहीं। 10186 2023 का R.Sahayarajan

वह दी गई शिकायत में अभियुक्तों

में से एक है

वी. गणेश कुमार द्वारा और उन्होंने

एक याचिका दायर की

एफ. आई. आर. को रद्द करने के

लिए उच्च न्यायालय के समक्ष

और एक के आधार पर आरोप पत्र

समझौता करें।

23 ] 8 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. श्री मुकुल रोहतगी, श्री कपिल सिब्बल, श्री सिद्धार्थ लूथरा और श्री सी. ए. सुंदरम, अलग-अलग पक्षों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हैं।

अभियुक्त, समान रूप से एक कोरस उठाया, मुखर रूप से आपत्ति जताई

उन अपीलार्थियों में से प्रत्येक द्वारा नए सिरे से जाँच के आदेश के विरुद्ध अपील की स्थिरता। उनका तर्क है कि एक आपराधिक अपराध की जांच सभी के लिए स्वतंत्र अभ्यास नहीं हो सकती है और कार्यवाही को चुनौती देने का अधिकार होना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, कुछ अपीलार्थी जो अजनबी हैं, न केवल बिना किसी अधिकार के अदालत में आए हैं, बल्कि अशुद्ध हाथों से आने के भी दोषी हैं जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि वे संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति बयानों की प्रतियां प्राप्त करने में भी कामयाब रहे हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि हमारे सामने कुछ अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल द्वारा स्थापित किए गए हैं और इसलिए, इस न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए

जिन व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है, उनके द्वारा दायर अपीलों पर विचार करें। 33. यह सच है कि आपराधिक न्यायशास्त्र पीड़ितों के लिए एक सीमित भूमिका को मान्यता देता है और यह राज्य है जिसे भारी भार सौंपा गया है।

अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने की जिम्मेदारी। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि कानून के कुछ सिद्धांत ऐसे समय में विकसित किए गए थे जब आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन की प्रक्रिया ईमानदार और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के हाथों में थी और

धारा काफी हद तक अप्रदूषित रही। आज की स्थिति अलग है। इस तरह के मामलों में, जहां कुछ शिकायतकर्ता और आरोपी एक अपवित्र गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आए हैं, अपराध के पीड़ितों को ऐसी साझेदारी की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। हमने इस मामले में देखा है कि सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, लोक सेवक व्यक्तियों के माध्यम से अवैध संतुष्टि का भुगतान करते हुए, सत्ता में बैठे व्यक्तियों को और बाद में अदालत के बाहर समझौते के आधार पर अभियुक्त का समर्थन करने के लिए अदालत में आते हैं। शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच केवल उनके विवादों से समझौता नहीं किया गया, बल्कि न्याय, निष्पक्षता, सद्भावना और आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों से समझौता किया गया। वास्तव में, हाथ में मामला वह है जहां केवल रिकॉर्ड के उद्देश्य से दो टीमें हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन किस टीम के लिए खेल रहा है और मैच कहाँ तय किया गया था।

34. वास्तव में, पी. धरमराज में मुकदमे के पिछले दौर में लोकस के सवाल पर बहुत मुखर प्रस्तुतियाँ की गई थीं।

आपराधिक अपील सं. में बनाम षण्मुगम 2। 1514-1516 2022 तक। लेकिन रखरखाव से संबंधित आपत्तियों को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था

1 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1186 वाई. बालाजी बनाम।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

इसलिए, यदि ऐसा व्यक्ति जिसने चयन में भाग लिया लेकिन जिसने लिया संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई भ्रष्ट प्रथाओं के कारण नियुक्ति नहीं मिलती है और जिन्होंने पहले ही आगे की मांग करने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी

जाँच का कोई अधिकार नहीं है, हम नहीं जानते कि और किसके पास होगा।

36. आपराधिक मामले की जांच और मुकदमे को शिकायतकर्ता और आरोपी द्वारा दोस्ताना मैच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगर उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो अंपायर ही अपना विकेट खो देगा।

37. कुछ अपीलार्थियों द्वारा प्रतियां दाखिल करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया था

अपीलों में कागजी पुस्तक के हिस्से के रूप में संहिता की धारा 164 के तहत स्वीकारोक्ति बयान। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति बयान पवित्र हैं और उनकी प्रतियां तीसरे पक्ष को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं और किसी भी तरह से, अपीलकर्ताओं ने यह भी नहीं बताया है कि क्या उन्होंने नियम, 2019 में निर्धारित किए गए तीसरे पक्ष के आवेदनों की प्रतिलिपि दायर की है और इन प्रतियों को आधिकारिक रूप से प्राप्त किया है।

38. रिलायंस को उनके तर्क के समर्थन में नियम, 2019 के नियम 207 (12) और नियम 210 पर रखा गया था। नियम 207 (12) और नियम 210 इस प्रकार हैं:

" 207 ( 12 ) अभियुक्तक स्वीकारोक्ति बयान दर्ज कयलाक बाद, मजिस्ट्रेट ओकर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षणमे ओकर दू टा फोटोकॉपी लेबाक व्यवस्था करत आ ओकरा सही प्रतिलिपिक रूपमे प्रमाणित करत।

मूल रूप से स्वीकारोक्ति कथन को एक विशेष संदेशवाहक के माध्यम से या द्वारा क्षेत्राधिकार न्यायालय को एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाएगा। देय स्वीकृति के साथ पंजीकृत पद। एक प्रमाणित प्रति [2023] 8 एस. सी. आर.

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती और अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं हो जाती, तब तक स्वीकारोक्ति बयान का उपयोग केवल जाँच के उद्देश्य के लिए करने और इसकी सामग्री को सार्वजनिक नहीं करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश के साथ जाँच अधिकारी को तुरंत मुफ्त में प्रस्तुत किया जाएगा। स्वीकारोक्ति कथन की अन्य प्रमाणित प्रति मजिस्ट्रेट की सुरक्षित अभिरक्षा में एक सीलबंद लिफाफे में रखी जाएगी।

210. तृतीय पक्ष द्वारा प्रतियों के लिए आवेदन। - कार्यवाही के किसी तीसरे पक्ष द्वारा न्यायालय की अभिरक्षा में निर्णय या आदेश या किसी कार्यवाही या दस्तावेज की प्रतियों के अनुदान के लिए आवेदन

केवल उस उद्देश्य को निर्दिष्ट करने वाले शपथ पत्र द्वारा समर्थित याचिका पर प्राप्त न्यायालय के आदेश द्वारा अनुमति दी जाएगी जिसके लिए

प्रतिलिपि की आवश्यकता है। "

39. नियम 207 (12) से यह स्पष्ट है कि जब तक जांच पूरी और अंतिम नहीं हो जाती, तब तक स्वीकारोक्ति बयान एक गोपनीय दस्तावेज है। रिपोर्ट दर्ज की गई। नियम 207 (12) के प्रासंगिक भाग में कहा गया है "। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और इसकी सामग्री को सार्वजनिक नहीं किया जाता है।

अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई "।

40. ऊपर निकाला गया नियम 210 तीसरे पक्ष को निर्णय या आदेश या किसी भी आदेश की प्रतियों के अनुदान के लिए न्यायालय में आवेदन करने में सक्षम बनाता है।

न्यायालय की अभिरक्षा में कार्यवाही या दस्तावेज "। इसलिए, ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने कुछ ऐसा दायर किया है जिसके लिए उनकी कभी कोई पहुंच नहीं हो सकती थी। यह एक विडंबना है कि जो लोग नकदी के लिए भारी नौकरियों के घोटाले का शिकार हुए हैं, उन पर आरोप है कि वे ऐसे लोग अशुद्ध हाथों के साथ अदालत में आए हैं जिनके हाथ कथित रूप से दूषित थे।

भ्रष्टाचार के पैसे के साथ।

41. वास्तव में, ठीक उसी समय से जब गोपी ने सी. आर. एल. में एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 2016 का ओ. पी. सं. 7503, वहाँ है

उच्च न्यायालय के समक्ष कई कार्यवाहियाँ की गई हैं जहाँ पक्षों ने

कई दस्तावेजों की प्रतियाँ जमा की। चयन को चुनौती देने वाले असफल उम्मीदवारों द्वारा रिट याचिकाएं भी दायर की गई थीं। उन मामलों में जांच अधिकारी द्वारा दायर काउंटर को इसके द्वारा निकाला गया है।

धर्मराज बनाम षण्मुगम 3 में दिनांकित 08.09.2022 निर्णय में न्यायालय। इसलिए, कई व्यक्तियों के कहने पर कई दस्तावेज सार्वजनिक क्षेत्र में दिखाई देने लगे हैं। अतः यह तर्क देना व्यर्थ है कि अपीलों को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि अपीलार्थी ऐसे दस्तावेज लेकर आए हैं जिनके लिए उनके पास कोई दस्तावेज नहीं हो सकते थे।

पहुँच।

8 आपराधिक अपील सं। 1514-1516 2022 का वाई. बालाजी बनाम।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

42. यद्यपि श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ वकील हैं।

इन अपीलों में से एक में अपीलार्थी की ओर से पेश होते हुए श्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल द्वारा स्थापित किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने 2015 की एफ़. आई. आर. No.441 में पहली शिकायत दर्ज होने के बाद शुरू हुई घटनाओं की समयरेखा पर भरोसा किया। हालाँकि हम इन विवरणों में नहीं जाना चाहते थे, हम कम से कम परिधि को छूने के लिए मजबूर हैं, ऐसा न हो कि हम बार के पार दिए गए तर्क से निपटने के लिए दोषी नहीं ठहराए जाएँ। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल द्वारा प्रदान की गई घटनाओं की समयरेखा इस प्रकार है:

10 व्यक्तियों के खिलाफ देवासगयम की शिकायत लेकिन

29.10.2015

मंत्री।

7 / 8.03.2016

एक गोपी और कई अन्य लोगों की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मंत्री, उनके भाई और उनके बहनोई ने नियुक्तियां करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग की।

गोपी द्वारा दायर 2016 के आपराधिक ओ. पी. No.7503 को अनुमति दी गई थी

20.06.2016

उच्च न्यायालय।

एफ. आई. आर. में संहिता की धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

13.06.2017

देवासगयम द्वारा 12 व्यक्तियों के खिलाफ केवल धारा 406, 419 और 420 के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया। मंत्री का नाम वहां नहीं था। मंत्री सेंथिल बालाजी ने 18 विधायकों के समूह का हिस्सा बनाया।

22.08.2017

राज्यपाल को एक पत्र सौंपा।

2017 की एफ. आई. आर. No.298 एक वी. गणेश की शिकायत पर दर्ज की गई।

09.09.2017

कुमार मंत्री और तीन अन्य लोगों के खिलाफ थे।  
मंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

18.09.2017

13.06.2018

मंत्री और तीन अन्य लोगों के खिलाफ 2017 की एफ. आई. आर. No.298 से उत्पन्न 2020 के सी. सी. No.19 में संज्ञान लिया गया था।

13.08.2018

अरुलमानी नाम के व्यक्ति ने मंत्री, उनके भाई अशोक कुमार और उनके पी. ए. षण्मुगम का नाम लेते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इसके परिणामस्वरूप 2018 की एफ. आई. आर. No.344 दर्ज की गई, हालांकि केवल निम्नलिखित अपराधों के लिए

आई. पी. सी. की धारा 406, 420 और 506

मंत्री दूसरे राजनीतिक दल में चले गए।

14.12.2018

2018 की एफ. आई. आर. No.344 में दायर अंतिम रिपोर्ट  
(कैलेंडर मामला बन जाता है)

12.04.2019

2021 का No.25)।

मंत्री सेंथिल बालाजी ने उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव जीता

23.05.2019

जिस पार्टी में वे 2018 में शामिल हुए थे।

एफ. आई. आर. से उत्पन्न 2021 के सी. सी. No.25 में  
संज्ञान लिया गया था।

27.11.2019

2018 का No.344।

सेंथिल बालाजी द्वारा आरोपमुक्त करने के लिए दायर याचिका  
खारिज कर दी गई है।

26.08.2020

26.02.2021

राज्य विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की जाती है। संहिता  
की धारा 173 (8) के तहत एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है।

08.03.2021

मंत्री और अन्य, न केवल आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए  
लेकिन पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए भी।  
संज्ञान 2021 के सीसी No.24 में लिया गया है।

01.04.2021

राज्य विधानसभा के आम चुनाव के परिणाम हैं -

02.05.2021

घोषित किया जाता है, सत्ता में पार्टी को बाहर कर दिया जाता  
है, एक नई व्यवस्था सरकार बनाती है और वह नए में मंत्री बन जाता है  
शासन।

जुलाई, 2021

एक रद्द याचिका दायर की जाती है और एक समझौता किया  
जाता है। उच्च न्यायालय ने 2021 के सीसी No.25 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि

30.07.2021

संयुक्त समझौता ज्ञापन।

23 ] 8 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. उपरोक्त घटनाओं की समयरेखा के आधार पर, श्री कपिल सिब्बल द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि मंत्री को इस मामले में फंसाया गया था।

08.03.2021, विधान सभा के चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए, क्योंकि वह सत्ता में पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए थे। इसलिए, यह दावा किया जाता है कि अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से राजनीतिक विरोधियों द्वारा मंत्री का पीछा करने के लिए स्थापित किया गया है।

44. लेकिन घटनाओं की उपरोक्त समयरेखा से हम केवल इतना ही समझ सकते हैं कि मंत्री के लिए परेशानी तब भी शुरू हुई जब वह एक राज्य में मंत्री थे। अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्था और अगस्त, 2017 में 18 विधायकों के समूह का हिस्सा बनने से पहले भी। यह याद रखना चाहिए कि

2016 के आपराधिक ओ. पी. No.7503 में आरोप, जिनका उच्च न्यायालय ने 20.06.2016 पर निपटारा किया था, ऐसे समय में लगाए गए थे जब वे पिछली सरकार में मंत्री थे और यह उनके एक साल से भी अधिक समय पहले हुआ था।

एक विभाजित समूह का हिस्सा बन गया। दिनांकित 20.06.2016 आदेश में, यह अनुच्छेद 6 में याचिकाकर्ता के वकील के तर्क के रूप में दर्ज किया गया था कि पुलिस ने यह देखा था कि मंत्री का नाम शिकायत में नहीं है, ताकि उसे बचाया जा सके। यह कि जांच अधिकारी ने वर्ष 2015 से आई. डी. 1 तक पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करने का विकल्प नहीं चुना, इसे मंत्री के श्रेय में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसे अभियोजन पक्ष के अपमान के रूप में लिया जाना चाहिए। अगर

पद की ढाल ने 2015 से उनकी रक्षा की जब तक कि वे अलग हुए समूह का हिस्सा नहीं बन गए और ढाल को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया गया जब तक कि वे अगले कार्यकाल में फिर से मंत्री नहीं बन गए।

शासन, इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला नहीं कहा जा सकता है। हमें नहीं पता कि अगर शिकायतकर्ता नई सरकार में फिर से मंत्री नहीं बनते तो क्या वे जुलाई, 2021 में समझौता कर लेते।

45. जनता दल बनाम एच. एस. में निर्णय अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किए गए चौधरी और सिमरजीत सिंह मान बनाम भारत संघ उनके बचाव में नहीं जाएंगे। यह न्यायालय आपराधिक अपील Nos.1514 में अपने दिनांकित 08.09.2022 निर्णय में स्थान के प्रश्न पर पहले ही विचार कर चुका है।

1516 पी. धरमराज (ऊपर) में 2022 का।

46. दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.10.2022 के आदेश की शुद्धता को चुनौती देने वाली हमारी दो अपीलें हैं।

9 (1992) 4 एससीसी 305

10 1 0 (1992) 4 एस. सी. सी. 653 बाई. बालाजी बनाम।



कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

वी. गणेश कुमार की शिकायत में अभियुक्त संख्या 3 के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन दोनों ने एक समझौता किया और सफलतापूर्वक फंस गए उच्च न्यायालय समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए।

सौभाग्य से, इस अदालत ने शिकायत को रद्द करने के आदेश को उलट दिया। फिर भी उन दोनों में नए सिरे से जाँच के आदेश पर हमला करते हुए इस न्यायालय के समक्ष आने का दुस्साहस है। 47. चिंताजनक बात यह है कि वी. गणेश कुमार परिवहन निगम के कर्मचारी हैं। उनकी शिकायत पर दायर आरोप-पत्र में, जिसे 2020 के सी. सी. No.19 के रूप में फाइल में लिया गया है, इस वी. गणेश कुमार के बारे में कहा गया है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार की राशि एकत्र की है।

ड्राइवर, कंडक्टर या मैकेनिक, जैसा भी मामला हो, के प्रत्येक पद के लिए रु. 2,00,000/- से रु. 4,50,000/- तक। हमें नहीं पता कि परिवहन निगम ने कम से कम उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की है या नहीं। अगर उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, तो

निगम को इस वी. गणेश कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, न केवल नौकरी-के-बदले-नकद घोटाले में पक्षकार होने के लिए, बल्कि निगम का कर्मचारी होने के बावजूद, नए सिरे से जांच के आदेश पर हमला करने के लिए इस अदालत में आने और आरोपी का समर्थन करने के लिए भी। दिलचस्प बात यह है कि नए सिरे से जांच के आदेश पर उनका हमला उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं है जिसे पीड़ित उसी आदेश को लागू करके प्राप्त करना चाहते हैं। पीड़ितों ने किया हमला

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए सिरे से जांच का आदेश

48. यही कारण है कि हमने वी. गणेश कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री वी. मोहना से बार-बार सवाल किया कि वी. गणेश कुमार अंततः चाहते हैं। इस सवाल का एकमात्र जवाब जो हमें मिला वह यह था कि नए सिरे से जांच का आदेश देने की शक्ति होनी चाहिए

यह कि यह वह मामला नहीं है जहाँ शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वी. गणेश कुमार अभी एक अलग शिविर में हैं।

49. इसलिए, उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.10.2022 के विवादित आदेश को चुनौती देने वाली अपीलें जहाँ तक कि वे आपराधिक के लिए पता लगाने योग्य हैं। 2021 के ओ. पी. No.15122 संबंधित हैं, अनुमति के योग्य हैं। तदनुसार, इन अपीलों की अनुमति दी जाती है और 31.10.2022 [2023] 8 एस. सी. आर. का आदेश दिया जाता है।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2021 के आपराधिक O.P.No.15122 में पारित किया गया है। 2021 का आपराधिक O.P.No.15122 खारिज हो जाएगा।

भाग-II (प्रवर्तन द्वारा कार्यवाही से संबंधित)

निदेशालय)

50. जैसा कि हमने घटनाओं के क्रम में बताया है, ईडी ने मामला दर्ज किया है

अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही 29.07.2021 पर एक सूचना रिपोर्ट संहिता की धारा 173 (8) के तहत, 2021 के सी. सी. No.24 में, पी. सी. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों सहित। यह अंतिम रिपोर्ट एफ. आई. आर. में थी

51. सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ईडी ने आरोपी को समन जारी करना शुरू कर दिया। ईडी ने दस्तावेजों की प्रतियां मांगने के लिए विशेष अदालत (विधेय अपराधों के मामले में) के समक्ष याचिकाएं भी दायर कीं। इन याचिकाओं को निचली अदालत द्वारा दिनांक 09.11.2021 के एक आदेश द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। विचारण न्यायालय के आदेश के भाग के विरुद्ध ई. डी. को अचिह्नित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों से वंचित करते हुए ई. डी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाएं दायर कीं। याचिकाओं को आंशिक रूप से उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा ईडी को नियम, 2019 के नियम 237 के तहत निरीक्षण करने की प्रक्रिया का पालन करने और उसके बाद विशेष न्यायालय के समक्ष एक नए तृतीय-पक्ष प्रतिलिपि आवेदन दायर करने की अनुमति दी गई थी।

ईडी। 53. मंत्री द्वारा 2022 के डब्ल्यू. पी. No.18213 में ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए दायर रिट याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि

अलिया: -

11 संक्षेप में "पीएमएलए"

वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

( i) कि उन्हें 2015 की एफ. आई. आर. Nos.441,2016 की 15,2017 की 298 और 2018 की 344 में गलत तरीके से फंसाया गया था;

( ii) 2016 की एफ. आई. आर. No.15 को पहले ही रद्द कर दिया गया था;

( iii) 2015 की एफ. आई. आर. Nos.441 और 2017 की 298 पर रोक लगा दी गई थी।

उच्च न्यायालय;

( iv) 2018 की उस एफ. आई. आर. No.344 को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था;

( v) कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पी. एम. एल. ए. की धारा 2 (1) (वाई) और धारा 3 की अनिवार्य आवश्यकताएं आकर्षित नहीं होती हैं;

( vi) कि ई. सी. आई. आर. का पंजीकरण उन शिकायतों पर आधारित था;

( vii) चूंकि वे शिकायतें रद्द करने की याचिकाओं में जांच का विषय हैं, इसलिए ईडी के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ( viii) कि पी. एम. एल. ए. की धारा 63 गलत जानकारी या जानकारी देने में विफलता के लिए सजा निर्धारित करती है और इसलिए समन

धारा 50 के तहत जारी किया गया बयान उसे विधेय अपराधों के मामलों में खुद को दोषी ठहराते हुए बयान देने के लिए मजबूर करेगा, जिससे उसका उल्लंघन होगा।

संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत उनके अधिकार;

( ix) कि ईडी ने अभियुक्तों के साथ अपराध की किसी भी आय की पहचान नहीं की थी, ताकि वे जांच के साथ आगे बढ़ सकें;

( x) कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष, ईडी इस आधार पर राज्य पुलिस के पास उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतियां चाहता था कि

ऐसे दस्तावेजों की प्रतियों के बिना, ईडी के लिए आगे बढ़ना संभव नहीं था।

( xi) कि ईडी द्वारा जांच की शुरुआत के द्वारा दूषित किया जाता है

54. ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में मुख्य रूप से इन पर ध्यान केंद्रित किया गया था: - ( i) विधेय अपराधों के लिए दो आपराधिक मामलों में आगे की कार्यवाही पर

रोक; [2023] 8 एस. सी. आर.

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( (ख) पूर्वनिर्धारित अपराध के लिए एक आपराधिक मामले को रद्द करना; और

( (iii) विशेष न्यायालय से बुनियादी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के बाद, वास्तव में अपराध की आय की पहचान किए बिना, ईडी का जंगल में जांच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास। हालाँकि, मौखिक सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ कानूनी दलीलें विकसित की गईं।

( (i) विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून।  
( (ख) किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अधिकारिता ग्रहण करने से पहले अधिकारिता संबंधी तथ्यों के अस्तित्व की आवश्यकता;

( (ग) एक अनुसूचित अपराध के रूप में आपराधिक गतिविधि के संयोजन की अनुपस्थिति, उससे अपराध की आय का सृजन।

और धन शोधन का कार्य, जो ईडी के लिए कदम उठाने के लिए अधिकार क्षेत्र तथ्य बनाता है; और  
( (iv) ईडी को बिना किसी सामग्री के मछली पकड़ने के अभियान पर जाने की अनुमति देने का खतरा।

56. यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उनका मामला विजय मदनलाल चौधरी (उपरोक्त) में निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया था। उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.09.2022 के आदेश के प्रासंगिक भागों को निकालना सार्थक होगा, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक अभियुक्त के वकील ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले पर भरोसा किया था।

57. आर. वी. अशोक कुमार, भाई के वकील का तर्क

उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 3 में मंत्री का विवरण इस प्रकार निकाला गया है:

" 3. Mr.Aryama सुंदरम, 2022 की रिट याचिका No.18209 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने शुरुआत में अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल का मामला विजय मदनलाल चौधरी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और उनके पक्ष में अन्य मामले (उपरोक्त) द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, फिर से आगे बढ़ रहे हैं।

तर्क दिया कि श्री आर. V.Ashok कुमार का भाई है

Mr.V.Senthil बालाजी, जो 2011 से 2015 की अवधि के दौरान पूर्व परिवहन मंत्री थे।

1 2 (2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 929 वाई. बालाजी बनाम।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

58. शनमुगम (अभियुक्त संख्या 3) की ओर से पेश वकील का तर्क उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निकाला गया है:

" 2. .... याचिकाकर्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि विजय मदनलाल चौधरी और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *v. भारत संघ और अन्य, 2022 (10) स्केल 577* ने अभिनिर्धारित किया है कि अपराध की आय के अभाव में, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं या कोई अभियोजन शुरू नहीं कर सकते हैं, इसलिए, रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए, विवादित कार्यवाही को रद्द करके।

59. इस प्रकार, विवादित आदेश से यह देखा जाता है कि तीन में से कम से कम दो अभियुक्तों ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उनके

विजय मदनलाल चौधरी में इस अदालत के फैसले में मामले को पूरी तरह से शामिल किया गया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश तर्क

हमारे सामने आगे बढ़ना विजय मदनलाल चौधरी में निर्णय की शुद्धता पर हमला साबित हुआ। हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि एक दृष्टिकोण से दूसरे दृष्टिकोण में यह दलबदल अनुसूची X द्वारा कवर किया गया है। हम केवल यह दिखाने के लिए इस तथ्य को दर्ज कर रहे हैं कि अधिकांश तर्क वास्तव में सुविधा के तर्क थे।

60. यह ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष क्या तर्क दिया, आइए अब देखें कि उच्च न्यायालय ने क्या किया। विवादित आदेश के पैराग्राफ 13 में, उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 187 (वी) (डी) के विशेष संदर्भ में विजय मदनलाल चौधरी पर ध्यान दिया। पैराग्राफ 14 में, उच्च न्यायालय ने विधेय के लिए शिकायत को रद्द करने पर ध्यान दिया एक मामले में अपराध और विधेय अपराधों से संबंधित अन्य दो मामलों में आगे की कार्यवाही पर रोक। पैराग्राफ 15 में, उच्च न्यायालय ने इस सवाल को संबोधित किया कि स्थगन आदेश का क्या प्रभाव पड़ता है। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि विशिष्ट अपराधों के संबंध में स्थगन आदेश के संचालन के दौरान पीएमएलए के तहत कार्यवाही की अनुमति दी जाती है, तो यह पक्षों की प्रतिष्ठा और सद्भावना को नुकसान पहुंचाएगा और इसलिए ईडी द्वारा जांच आगे नहीं बढ़ सकती है। विवादित आदेश के पैराग्राफ 16 में, उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि अन्य

तीन एफ. आई. आर. एस. के अलावा, ईडी के पास पी. एम. एल. ए. के तहत आगे बढ़ने के लिए और कुछ नहीं था। पैराग्राफ 17 में, उच्च न्यायालय ने अधिकारिता संबंधी तथ्यों के अस्तित्व से संबंधित विवाद को दर्ज किया और पैराग्राफ में अरुण कुमार बनाम भारत संघ के फैसले का उल्लेख किया।

13 (2007) 1 एस. सी. सी. 732 [2023] 8 एस. सी. आर.

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. इसके बाद, उच्च न्यायालय पैराग्राफ 20 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक आपराधिक मामले में शिकायत को रद्द करने और अन्य दो कैलेंडर मामलों में कार्यवाही पर रोक से पता चलता है कि ईडी के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार तथ्य या कार्रवाई का कारण नहीं था।

61. चूंकि हमारे सामने बहुत सारे तर्क दिए गए थे जैसे कि ईडी अधिकार क्षेत्र के तथ्यों के अस्तित्व के बिना आगे बढ़ा, यह है यह दिखाने के लिए कि उच्च न्यायालय ने क्या अधिकारिता तथ्य माना है, विवादित आदेश के पैराग्राफ 20 को निकालना आवश्यक है। इसलिए, आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 20 को इस प्रकार निकाला गया है:

" 20. उपरोक्त निर्णय का केवल अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्षेत्राधिकार तथ्य का अस्तित्व सीमित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। इसलिए, वर्तमान मामलों में, जब कार्रवाई का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कैलेंडर मामलों में से एक में कार्यवाही को 2021 की आपराधिक मूल याचिका संख्या 13374 में दिनांकित आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था और दो अन्य कैलेंडर मामलों में कार्यवाही पर इस न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है, तो प्रतिवादी/विभाग के लिए दो प्राथमिकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश की अवधि के दौरान कोई कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार तथ्य या कार्रवाई का कारण नहीं है। विज।

2021 का C.C.No.19/2020 और C.C.No.24 "।

62. फिर से, पैराग्राफ 22 में, उच्च न्यायालय ने एक राय दर्ज की कि स्थगन की मंजूरी कार्यवाही को ग्रहण करने के बराबर होगी।

इसलिए, इस एकमात्र आधार पर, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैराग्राफ 22 में निष्कर्ष निकाला कि ईडी को आपराधिक शिकायतों को रद्द करने के लिए कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी, जिसमें एक स्थगन आदेश लागू था। लेकिन उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दे रहा था और उच्च न्यायालय ने सभी प्रश्नों को उचित कार्यवाही में निपटाने के लिए छोड़ दिया।

63. अंततः, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैराग्राफ 23 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

" 23. .... इसलिए, जैसा कि हमने निष्कर्ष निकाला है कि 2021 के C.C.No.25 में कार्यवाही को रद्द करने और 2020 के C.C.No.19 और 2021 के C.C.No.24 में कार्यवाही पर रोक लगाने के मद्देनजर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्तमान के लिए अनुसूचित अपराध को ग्रहण कर लिया गया है, निलंबित कर दिया गया है या ठहराव की अवधि के दौरान काम करना बंद कर दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग को उक्त वाई. बालाजी बनाम की अंतिमता की प्रतीक्षा करनी होगी।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

कार्यवाही। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या 2020 के C.C.No.19 और 2021 के C.C.No.24 में कार्यवाही को संबंधित व्यक्तियों द्वारा दायर आवेदनों में दिए गए आदेशों के अनुसार रद्द कर दिया गया है।

कार्यवाही, जिस स्थिति में, प्रत्यर्थी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कदम नहीं उठा सकता है या कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है, जैसा कि विजय मदनलाल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है।

चौधरी और अन्य और पार्वती कोल्लूर में और एक अन्य वी। राज्य

प्रवर्तन निदेशालय, 2022 लाइव लॉ (एससी) 688 ने उपर्युक्त का हवाला दिया। इसलिए, प्रत्यर्थी को 2021 के आपराधिक संशोधन मामले No.224, आपराधिक मूल याचिका के निपटारे तक, ईसीआईआर/एम. डी. एस. जेड. ओ./21/2021 में आक्षेपित कार्यवाही के अनुसार आगे बढ़ने से रोक दिया गया है।

2021 की No.15122 और 2022 की SLP (CRL) डायरी No.9957

( 2022 का एसएलपी (सीआरएल) No.3841)। ”

जांच पड़ताल की। 65. इसलिए, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने दिनांकित 01.09.2022 के विवादित आदेश में केवल एक अस्थायी राहत दी है।

ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ आरोपी को। आज, मंत्री द्वारा अपनी आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज करने के खिलाफ दायर 2021 के आपराधिक संशोधन मामले No.224 को उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 31.10.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। यद्यपि देवासगयम द्वारा दायर 2021 के आपराधिक ओ. पी. No.15122 को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है, उसी दिनांकित 31.10.2022 आदेश द्वारा, उक्त आदेश को हमारे द्वारा इस निर्णय के भाग 1 में दरकिनार कर दिया गया है।

66. जहाँ तक एसएलपी (सी. आर. एल.) का संबंध है। 2022 का No.3941 2022 की डायरी No.9957 संबंधित है, यह उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश से उत्पन्न होता है

30.03.2022 , जो फिर से वर्तमान अपीलों का विषय है।

67. दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने रद्द नहीं किया है

ईडी द्वारा जारी समन। उच्च न्यायालय ने ईडी को केवल तब तक आगे की कार्यवाही करने से रोक दिया था जब तक कि विधेय अपराधों से संबंधित मामलों में बाधा दूर नहीं हो जाती।

23 ] 8 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

68. दिलचस्प बात यह है कि किसी भी आरोपी ने उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.09.2022 के आदेश को चुनौती देने के लिए कोई अपील नहीं की है।

कि उच्च न्यायालय को अन्य आधारों पर ईडी द्वारा जारी समन को कुल मिलाकर रद्द कर देना चाहिए था। इसके बजाय, अभियुक्त केवल दिनांकित 01.09.2022 के विवादित आदेश का बचाव करने के लिए वकील के माध्यम से पेश हुआ।

69. इसलिए, कानून में, (i) एक बार जब आरोपमुक्त करने के लिए याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया जाता है।

2021 का मामला No.224; (ii) आपराधिक ओ. पी. में एक बार नए सिरे से जांच का आदेश। 2021 का No.15122 दरकिनार कर दिया गया है; (iii) दस्तावेजों की प्रतियों को सुरक्षित करने के लिए ईडी के अधिकार से संबंधित उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.03.2022 के आदेश पर विचार करने के बाद; (iv) एक बार उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.07.2021 के आदेश को एक आपराधिक मामले को रद्द करने के बाद; और (v) एक बार जब विधेय अपराधों के लिए दो आपराधिक मामलों में चल रही रोक को खाली कर दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विवादित आदेश में दी गई अस्थायी छूट अपने आप चली जाएगी। कानून में इस कठिनाई को महसूस करते हुए, अभियुक्तों ने हमारे सामने गीत का विषय पूरी तरह से बदल दिया, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें इस रूप में नियुक्त किया गया था अपीलों में उत्तरदाता केवल उच्च न्यायालय के विवादित आदेश का समर्थन करते हैं।

70. वास्तव में, पी. एम. एल. ए. मामले में सभी अभियुक्तों की ओर से पेश होने वाले सभी विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने बड़ी मंजूरी के लिए आगे की दलीलें दीं।

विवादित आदेश के तहत उन्हें जो राहत मिली, उसके खिलाफ कोई अपील दायर किए बिना। कानून में एक सफल पक्ष (हालांकि दीवानी कार्यवाही में) के लिए निर्णय का समर्थन किए बिना डिफेंडी का समर्थन करना संभव है। लेकिन अभियुक्त ने हमारे सामने जो करना चाहा वह निर्णय का समर्थन करना और आदेश के विस्तार की मांग करना था। स्वतंत्र रूप से अपील दायर करना। चूंकि उन्होंने इस तरह का मार्ग अपनाकर एक मौका लिया था, इसलिए वे इसके बाद के विवादित आदेश को चुनौती देने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं, एक बार जब इस न्यायालय द्वारा उस पर अनुमोदन की मुहर लगा दी जाती है और विलय का सिद्धांत लागू हो जाता है।

71. हम इसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि हम उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश को चुनौती देने वाली सभी अपीलें को खारिज करते हैं।

01.09.2022 , तब उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.10.2022 के आदेश को चुनौती देने वाले हमारे आदेश के दूसरे भाग के परिणामस्वरूप स्वतः ही उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा ईडी मामले में अपने दिनांकित 01.09.2022 के आदेश द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा को हटा लिया जाएगा। इसलिए, हमारे लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि हम उनकी ओर से उठाए गए विवादों से निपटें। अभियुक्त को अधिक राहत पाने के उद्देश्य से। लेकिन हम इस मार्ग को अपनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए, हम उठाए गए तर्कों को संबोधित करेंगे।



वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

## 72. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल की दलीलें

ये हैं:

( (i) धन शोधन के अपराध का गठन करने के लिए, किसी को यह करना होगा कि

अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल हैं;

( (ii) सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के लिए आधार बनने वाली तीन प्राथमिकियों में से किसी में भी कोई आरोप नहीं था -

अपराध की आय का सृजन या धन शोधन का अपराध;

( (iii) कि ईडी के पास कभी भी संदेह करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी

कि अभियुक्त ने अपराध की आय से संबंधित कोई भी गतिविधि की है;

( (iv) यही कारण है कि ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर दस्तावेजों की प्रतियों की मांग की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कुछ हो सकता है

किसी अन्य कानून के प्रावधानों के बारे में और इसके विपरीत नहीं; ( (vi) विजय मदनलाल में पीएमएलए के प्रावधानों की व्याख्या करने के तरीके में बहुत सारे अंतर्निहित विरोधाभास हैं।

चौधरी; ( (vii) यद्यपि पी. एम. एल. ए. की धारा 50 (2) निदेशक और उसके अधीनस्थों को किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार देती है, चाहे वह साक्ष्य दे या न दे।

जाँच के दौरान कोई भी अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

विजय मदनलाल चौधरी ने कहा कि यह वास्तविक जांच नहीं है।

भावना;

( (viii) कि पीएमएलए की धारा 50 (2) के तहत शक्ति संहिता की धारा 160 के तहत पुलिस अधिकारी की शक्ति के समान है;

( (ix) कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 द्वारा पी. एम. एल. ए. के संशोधन के साथ डब्ल्यू. ई. एफ. 01.08.2019, पुरुष अधिकार की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था।

के साथ और संशोधन द्वारा जोड़े गए स्पष्टीकरण ने सभी प्रक्रियाओं या गतिविधियों को बनाया जैसे कि छिपाना, कब्जा, अधिग्रहण, उपयोग, प्रक्षेपण बेदाग संपत्ति के रूप में और बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, जो विकल्प में उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, जबकि धारा 3 का मुख्य भाग "और" संयोजन का उपयोग करता है, धारा के तहत स्पष्टीकरण "या"; [2023] 8 एस. सी. आर. अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।



## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( x ) कि धारा 3 का संशोधन पूरी तरह से इसके विपरीत है

बिहटा को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड केन मार्केटिंग यूनियन Ltd.vs में निर्धारित कानून। बैंक ऑफ बिहार 1 4, इस प्रभाव से कि एक स्पष्टीकरण मुख्य खंड के दायरे को व्यापक नहीं बना सकता है;

( xi ) कि पी. एम. एल. ए. केवल वहीं लागू होता है जहां अपराध की आय का शोधन किया जाता है, हालांकि अपराध की आय का अस्तित्व एक

पी. एम. एल. ए. के तहत अपराध करने के लिए कोई शर्त नहीं है; ( xii ) कि यदि ईडी के पास केवल इस जानकारी के आधार पर जांच करने का अधिकार क्षेत्र है कि अपराध की आय से जुड़ा एक पूर्वनिर्धारित अपराध किया गया है, तो यह ईडी को राज्य पुलिस के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सशक्त बनाने के बराबर होगा, जिससे संघीय ढांचे में दरारें पैदा होंगी।

( xiii ) कि आय की मात्रा को निर्दिष्ट/पहचाने बिना और आय के बिना अपराध की आय का मात्र अस्तित्व।

धनशोधन के अपराध को धनशोधन का अपराध नहीं माना जा सकता है।

( xiv ) कि विजय मदनलाल चौधरी में यह गलत निर्णय लिया गया था कि यह एक दंडात्मक कानून नहीं था, हालांकि अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति पर धन शोधन के अपराध के लिए मुकदमा चलाना और दंडित करना है;

( xv ) कि संहिता के तहत उपलब्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय भी उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए विजय मदनलाल चौधरी को नहीं दिया गया है।

सही निर्णय लिया। विद्वान वकील ने निर्णय में पैराग्राफ 159,163,168 और 172 जैसे कई अंशों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। विजय मदनलाल चौधरी और यह तर्क दिया गया कि यह गलत तरीके से तय किया गया था।

73. वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल के अनुसार, वर्तमान कार्यवाही में कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। वे इस प्रकार हैं:

ई. डी. के लिए शुरू करने के लिए क्या अधिकार क्षेत्र की पूर्वापेक्षाएँ हैं?

पीएमएलए के तहत जांच?

क्या ईडी के पास केवल इस आधार पर विधेय अपराध की जांच करने वाले अधिकारियों से जानकारी लेने की शक्ति है कि एक विधेय अपराध की जांच चल रही है, यहां तक कि कोई ऐसी जानकारी प्राप्त किए बिना भी जो संज्ञेय अपराध है।

पी. एम. एल. ए. के तहत अपराध हुआ है और हो रहा है

14 एयर 1967 एससी 389 वाई. बालाजी बनाम।



कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

ऐसी सामग्री रखना जो धन शोधन के अपराध का संकेत देती हो?

क्या अपराध की आय का अस्तित्व ई. डी. को जाँच शुरू करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकता है?

"मनी लॉन्ड्रिंग" के तत्व क्या हैं?

ईडी को धारा 50 के तहत समन जारी करने का अधिकार देने से पहले किन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है? पीएमएलए?

क्या धारा 50 पी. एम. एल. ए. के तहत समन किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जो पी. एम. एल. ए. के तहत आरोपी है।

या विधेय अपराध में?

❖

क्या पीएमएलए की धारा 50 और 63 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है?

संविधान के Art.20 (3) और 21 के तहत सुरक्षा उपाय?

74. कानून में अपरिहार्य स्थिति को स्वीकार करते हुए कि दो सदस्यीय पीठ के रूप में, हम तीन सदस्यीय पीठ के निर्णय से बाध्य हैं। विजय मदनलाल चौधरी, श्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मामले को हल करने के लिए तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष रखा जा सकता है।

पीएमएलए द्वारा बनाई गई पहली। इस संबंध में, उन्होंने भारत संघ बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड में एक अन्य तीन सदस्यीय पीठ के फैसले के पैराग्राफ 113 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें इस अदालत ने एक राय व्यक्त की कि विजय मदनलाल चौधरी में जब्त की कार्यवाही के संबंध में निर्धारित अनुपात के तहत

पी. एम. एल. ए. की धारा 8, एक उपयुक्त मामले में आगे की व्याख्या की आवश्यकता है।

मामला और कि इस तरह के स्पष्टीकरण के बिना, मनमाने ढंग से आवेदन के लिए बहुत गुंजाइश बची है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक रिट याचिका में इस न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ द्वारा पारित एक आदेश की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया लेखन याचिका (सी. आर. एल.) 2023 का No.65, पीएमएलए के कुछ प्रावधानों को चुनौती देता है। दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने उक्त रिट याचिका को तब रखने का निर्देश दिया जब पीठ तीन न्यायाधीशों के संयोजन में बैठेगी। इसे तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष रखे जाने के बाद, रिट याचिका में नोटिस का आदेश दिया गया था। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से उत्पन्न वर्तमान अपीलों को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जा सकता है।

75. संक्षेप में, श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील की उपरोक्त सभी दलीलों का उद्देश्य हमें यह विश्वास दिलाना है कि विजय

5 (2023) 3 एस. सी. सी. 315 [2023] 8 एस. सी. आर.

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मदनलाल चौधरी पर गलत निर्णय लिया गया था और इसलिए हम इसे एक बड़ी पीठ के पास भेज सकते हैं।

76. अभियुक्तों में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया: -

( i) जब ई. सी. आई. आर. पंजीकृत किया गया था, तब ई. डी. के पास आवश्यक मूलभूत सामग्री नहीं थी, जैसा कि उन्होंने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया था।

( ii) कि विधेय अपराध के लिए एफ. आई. आर. एस. और ई. सी. आई. आर. दोनों के पंजीकरण में लंबी देरी हुई है;

लेकिन देवासगयम द्वारा दायर एफ. आई. आर. के अलावा अन्य एफ. आई. आर. वर्ष की थीं। 2017 और 2018 और ईसीआईआर वर्ष 2021 में पंजीकृत किया गया था;

( iv) कि ईडी की ओर से इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

देरी;

( v) कि धन शोधन को प्रथम दृष्टया भी अपराध बनाना।

प्रत्यक्षतः, तीन चीजें आवश्यक हैं, अर्थात् (i) अपराध करना, जो एक अनुसूचित अपराध है, (ii) अपराध की आय का सृजन; और (iii) उन आय का धनशोधन, और इन तीन मूलभूत तथ्यों में से कोई भी इस मामले में मौजूद नहीं है।

77. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें वास्तव में दो प्रकार की हैं, अर्थात् (i) एक अधिकार क्षेत्र तथ्य के अभाव में, जो ईडी द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए एक अनिवार्य या शर्त पूर्ववर्ती है, ईडी द्वारा जारी समन जाना चाहिए; या वैकल्पिक रूप से (ii) विजय मदनलाल चौधरी में निर्णय में निहित अंतर्निहित विरोधाभासों को देखते हुए और इस अदालत के नोटिस का आदेश देने के मद्देनजर।

पुनरीक्षण याचिका में, अपीलों को भी एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।

78. उनके इस तर्क के समर्थन में कि एक क्षेत्राधिकार तथ्य का अस्तित्व ईडी द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है, विद्वान वरिष्ठ वकील शौकीन सिंह बनाम देसा में निर्णयों पर निर्भर करते हैं।

सिंह 1 और अरुण कुमार बनाम भारत संघ "।

16 ( 1970 ) 3 एस. सी. सी. 881  
बालाजी बनाम।

17 7 ( 2007 ) 1 एस. सी. सी. 732 वाई.

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

80. यह दिखाने के लिए कि इस न्यायालय द्वारा समीक्षा के लिए एक याचिका पर विचार किया गया है, विद्वान वरिष्ठ वकील समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) में इस न्यायालय की कार्यवाही के रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। 2022 का No.219 कार्ति पी. चिदंबरम बनाम में। प्रवर्तन निदेशालय। 81. अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि जब कानून के कुछ प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है, तो बाद के सभी मामलों को टैग किया जाना चाहिए या

स्थगित कर दिया। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील भरोसा करते हैं

जयराम रमेश बनाम भारत संघ 2 0, थॉमस फ्रेंको राजेंद्र देव 2 1 बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर। भारत संघ, कांतारू राजीवरु (धर्म का अधिकार, पुनः-9 जे) बनाम भारतीय युवा वकील संघ 22, असगर अली बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 2,3 और

दाउदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2 4. 82. यह तर्क देते हुए कि जब ईडी द्वारा कार्यवाही की शुरुआत अधिकार क्षेत्र के तथ्यों के अस्तित्व के बिना थी, तो बाद की सभी कार्रवाइयां, जैसे कार्ड का एक पैकेट गिरना चाहिए, विद्वान वरिष्ठ वकील लैटिन मैक्सिम सबलाटो फंडामेंटो क्रेडिट ओपस पर निर्भर करता है जिसका अर्थ है कि "यदि प्रारंभिक कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो सभी बाद में और

परिणामी कार्यवाही होती है "। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: ( i ) बन्नीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार 2 5 25; (ii) केरल राज्य बनाम पुथेनकावु एन. एस. एस. करयोगम 2,6; और (iii) पंजाब राज्य बनाम। देविंदर पाल सिंह भुल्लर 2 7.

83. अभियुक्तों में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम ने एक अलग तर्क अपनाया। विजय मदनलाल चौधरी की शुद्धता पर हमला करने के बजाय, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया: 18 82022 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 514

19 सीआरएल। अपील No.1254/2022 dt.16.08। 2022 20 2019 का एसएलपी (सी) No.13103

21 डब्ल्यूपी (सी) No.366/2022 दिनांक 12.05.2022 22 (2020) 9 एससीसी 121 23 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 3095

24 42023 एससीसी ऑनलाइन एससी 129

25 ( 2000 ) 8 एस. सी. सी. 395 26 ( 2001 ) 10 एससीसी 191

27 ( 2011 ) 14 एससीसी 770 [2023] 8 एस. सी. आर.

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

- ( i) कि पी. एम. एल. ए. का उद्देश्य धन शोधन को रोकना है;  
( ii) धन शोधन का अपराध होने के लिए, एक व्यक्ति

अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में खुद को शामिल करना चाहिए; ( (ग)  
ई. डी. अपराध की आय की पहचान के बाद ही अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर सकता है।

( (iv) कि ईडी का अधिदेश धन शोधन के अलावा अन्य अपराधों के लिए किसी पर मुकदमा चलाने तक नहीं फैला है;

( vi) कि किसी ऐसी संपत्ति की पहचान के बिना, जो अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करती है, कार्यवाही शुरू करने के लिए एक क्षेत्राधिकार तथ्य शुरू नहीं होता है; ( vii) कि सूचना रिपोर्ट दर्ज किए बिना धारा 50 के तहत कोई समन जारी नहीं किया जा सकता है;

( viii) कि धारा 50 (2) के तहत समन जारी करने की शक्ति का प्रयोग केवल किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान किया जा सकता है।

अधिनियम;

( ix) कि हाथ में मामले में, आय का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई संपत्ति नहीं है

अपराध की पहचान की गई है;

( x) यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने ईडी से सवाल किया कि धारा 3 कैसे लागू की गई; और

( xi) कि इसलिए ईडी द्वारा कार्यवाही की शुरुआत को विजय में व्याख्या किए गए कानून की रूपरेखा के भीतर भी बनाए नहीं रखा जा सकता है। मदनलाल चौधरी।

84. अंत में, अभियुक्तों में से एक की ओर से वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम ने तर्क दिया कि हालांकि उच्च न्यायालय ने अनुमति दी

अब तर्क दिए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों के लिए अभियुक्त की प्रार्थना, उच्च न्यायालय के समक्ष सफल पक्ष हमेशा विवादित आदेश में बताए गए आधारों के अलावा अन्य आधारों पर निर्णय को बनाए रखने की कोशिश कर सकता है। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील उत्तर रेलवे कंपनी के प्रबंधन में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, राजस्थान, जयपुर 2 8.

( i) कि धन शोधन के अपराध को वैश्विक समुदाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ के अपराध के रूप में माना जाता है, जो धन शोधन को प्रभावित करता है। राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएँ;

( (ii) कि कानून का पता पालेर्मो और वियना सम्मेलनों से लगाया जा सकता है;

( (ग) इन समझौतों के परिणामस्वरूप वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की स्थापना हुई।

( (iv) कि उपरोक्त समझौतों और एफ. ए. टी. एफ. के गठन के बाद लंबे समय तक भारत में धन पर अंकुश लगाने में कमी पाई गई।

धन शोधन और इसलिए धन शोधन रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक मूल्यांकन के लिए कुछ सिफारिशों की गई; ( (V) उनके द्वारा की गई सिफारिशों को अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके लागू किया गया था;

( vi) विजय मदनलाल चौधरी में अधिनियम के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और उसके संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई है;

( vii) कि पी. एम. एल. ए. के लगभग सभी प्रावधानों को विजय मदनलाल चौधरी में चुनौती दी गई थी और प्रत्येक आधार पर हमला किया गया था।

प्रावधानों पर तीन सदस्यीय पीठ द्वारा विस्तार से विचार किया जाता है;

( viii) कि चेरी में कई बार काटने का प्रयास नहीं किया जा सकता है; ( ix) कि एक बड़ी पीठ के निर्णय की शुद्धता पर संदेह करके, एक के आवेदन पर अनिश्चितता का बादल नहीं बनाया जा सकता है

कानून; ( X) कि विजय मदनलाल चौधरी में निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल है और टकटकी निर्णय के सिद्धांत को अर्थ दिया जाना चाहिए।

( xi) कि अंग्रेजी टकटकी निर्णय के सिद्धांत पर पूर्ववर्ती है, जैसे कि स्ट्रीट ट्रामवेज बनाम लंदन काउंटी काउंसिल 3 0 और रेडक्लिफ बनाम रिबल मोटर सर्विसेज 3 1, का हमारे न्यायालयों ने अनुसरण किया है;

28 ( 1967 ) 2 एससीआर 476

29 संक्षेप में "एफ. ए. टी. एफ".

30 ( 1898 ) एसी 375 (378)

31 ( 1939 ) एसी 215 (245)

23 ] 8 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( xii) कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा साक्षी बनाम भारत संघ 3 2 में निर्धारित किया गया है, टकटकी निर्णय का सिद्धांत कानून को निश्चितता देता है और लोगों का मार्गदर्शन करता है

भविष्य में अपने मामलों को ढालें;

( xiii) कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दाउदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य 3 3 में अभिनिर्धारित किया गया है, कम कोरम की एक पीठ बड़े कोरम की पीठ द्वारा लिए गए विचार की शुद्धता पर असहमति व्यक्त या सवाल नहीं उठा सकती है;

86. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। तीनों विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण श्री कपिल सिब्बल, श्री सी. ए. सुंदरम और श्री सिद्धार्थ लूथरा नाम के अभियुक्तों की ओर से पेश होने से पता चलता है कि उनकी तीन-आयामी रणनीति है।

द्वारा कार्यवाही की शुरुआत पर उनके हमले में तैयार किया गया था

ईडी। यह त्रि-आयामी रणनीति इस प्रकार है:

( i) विजय मदनलाल चौधरी में निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाना और वृहद पीठ (श्री कपिल द्वारा) को संदर्भित करने की मांग करना। सिब्बल);

( (ii) विजय मदनलाल चौधरी में निर्णय को सही स्वीकार करना और यह प्रदर्शित करने की कोशिश करना कि कैसे वर्तमान मामले में कार्यवाही की शुरुआत विजय मदनलाल चौधरी (श्री सी. ए. सुंदरम द्वारा) में अनुपात के अनुरूप नहीं है। और

( iii) कुछ हिस्सों पर भरोसा करना, लेकिन विजय मदनलाल चौधरी के कुछ अन्य हिस्सों पर हमला करना ताकि इनमें से कोई भी एक भागने का मार्ग (श्री लूथरा द्वारा)।

32 ( 2004 ) 5 एस. सी. सी. 518  
बनाम।

33 ( 2005 ) 2 एस. सी. सी. 673 वाई. बालाजी

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

87. मुद्दों के संदर्भ में, तीनों विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्पष्ट किया जा सकता है और दो में तैयार किया जा सकता है

बुनियादी प्रश्न जिनका हमें समाधान करना पड़ सकता है। ये प्रश्न इस प्रकार हैं -

इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह इन अपीलों को समीक्षा याचिका के साथ संलग्न करे या इन मामलों की सुनवाई को तब तक स्थगित करे जब तक कि समीक्षा याचिका और अन्य याचिकाओं में कोई निर्णय नहीं दिया जाता है?

88. इन दोनों प्रश्नों का उत्तर खोजने से पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पीएमएलए कैसे और क्यों अस्तित्व में आया और क्या

भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने भारत को कानून लाने के लिए मजबूर किया। मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय 3 4, दक्षिण एशिया के अनुसार, भ्रष्टाचार को दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शासन और सुरक्षा चुनौती के रूप में पहचाना जाता है। यू. एन. ओ. डी. सी. ने अनुमान लगाया है कि भ्रष्टाचार की लागत वैश्विक जी. डी. पी. के 5 प्रतिशत से अधिक (26 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) सालाना है, जिसमें वैश्विक धन शोधन का अनुमान लगभग 500 अरब डॉलर (40 लाख करोड़ भारतीय रुपये) सालाना है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने दिनांकित संस्करण में बताया कि पुणे स्थित फॉरेंसिक अकाउंटिंग कंपनी द्वारा "इंडिया फॉरेंसिक" नाम से वर्ष 2011 में "मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में भारत में भ्रष्टाचार के आकार को प्रमाणित करने" पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर। 17.07.2011 दशक 2001-2010 में भारत से बाहर धनशोधन किया गया धन Rs.18,86,000 करोड़ आंका जा सकता है। यही कारण है कि मई 2011 में भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हिस्सा बना।

( यू. एन. सी. ए. सी.) 160 से अधिक अन्य देशों में शामिल हो रहे हैं जो इस यू. एन. कन्वेंशन के पक्षकार थे।

89. मनी लॉन्ड्रिंग पर कानून का इतिहास लगभग छह दशक पुराना है। संक्षेप में, इस इतिहास का पता इस प्रकार लगाया जा सकता है:

( i) 1961 में, नशीली दवाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था

इसे अपनाया गया और वर्ष 1972 के प्रोटोकॉल द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

34 संक्षेप में, "UNODC"

23 ] 8 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( ii) 1971 में, साइकोट्रोपिक पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

पदार्थ बनाए गए थे।

( iii) 1974 में, जर्मनी में हर्स्टैट बैंक के नाम से जाने जाने वाले एक बैंक को नियामकों द्वारा परिसमापन के लिए मजबूर किया गया था। जिस दिन यह हुआ, कई बैंकों ने इसके बदले में हर्स्टैट को भुगतान जारी किया था।

( iv) दिसंबर 1988 में दो चीजें हुईं। एक अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि के नाम से एक संधि को अपनाना था। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेस (लोकप्रिय रूप से वियना कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है)। दूसरा यह था कि लगभग उसी समय, बासेल समिति ने नैतिक सिद्धांतों का एक सामान्य बयान जारी किया जो बैंकों के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उनके संस्थानों के साथ व्यापार करने वाले सभी व्यक्तियों की ठीक से पहचान की जाए, जो लेनदेन वैध नहीं लगते हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग प्राप्त किया जाए।

( v) 1989 में पेरिस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में एफ. ए. टी. एफ. की स्थापना सदस्य देशों द्वारा एक अंतर-सरकारी निकाय के रूप में की गई थी।

कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। अब एफ. ए. टी. एफ. में भारत सहित 39 सदस्य हैं और दुनिया भर के 200 से अधिक क्षेत्राधिकार एफ. ए. टी. एफ. की सिफारिशों के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

( vi) 1990 में, यूरोप की परिषद के सदस्य राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसकी पुष्टि की, जिसे द कन्वेंशन ऑन लॉन्ड्रिंग के नाम से जाना जाता है। अपराध से प्राप्त आय की खोज, जब्ती और जब्ती, जिसे स्ट्रासबर्ग कन्वेंशन या सीईटीएस 141 के रूप में भी जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया

हालाँकि वे यूरोप की परिषद के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसकी पुष्टि की। कन्वेंशन ने अपराध की जांच करने और उसकी आय का पता लगाने, जब्त करने और जब्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपसी सहायता को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया। राज्यों को एक साथ लाने का उद्देश्य पूर्ण विधायी सद्भाव के अभाव में भी समान स्तर की दक्षता प्राप्त करने में उनकी सहायता करना था।

वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

( vii) मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के हिस्से के रूप में, धन शोधन के खिलाफ एक वैश्विक कार्यक्रम (जी. पी. एम. एल.) की स्थापना की गई थी।

( viii) 15.11.2000 पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसे खोला गया दिसंबर 2000 में पालेर्मो, इटली में आयोजित एक उच्च स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन में सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए (जिसे अब पालेर्मो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है)।

2005 में लागू किया गया। ( x) 8 से 8 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा के अनुसार

10 जून 1998 (जिसमें भारत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है)

( संशोधन) अधिनियम, 2012 (डब्ल्यू. ई. एफ. 15-02-2013)। ( xi) क्षेत्राधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने विधायी ढांचे को तैयार या उन्नत करने में सहायता करने के प्रयास के हिस्से के रूप में और

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उपायों को लागू करने और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं, यू. एन. ओ. डी. सी. ने 2003 में जारी किया, "मॉडल मनी लॉन्ड्रिंग, अपराध की आय और आतंकवादी वित्तपोषण।

बिल "।

धनशोधन, आतंकवादी वित्तपोषण, निवारक उपाय और अपराध की आय "। संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून 2009 के कुछ प्रावधानों से पता चलता है कि पीएमएलए को मॉडल कानून के अनुरूप लाया गया है। 91. मॉडल कानून में निहित स्व-शोधन पर मसौदा टिप्पणी इस सवाल से संबंधित है कि क्या किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से [2023] 8 एस. सी. आर. होना चाहिए।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधेय अपराध में आरोपित किया जाता है ताकि अपराध एक-धनशोधन में अभियुक्त हो। वह इस प्रकार है:

" सेल्फ-लॉन्ड्रिंग:

" जैसा कि धारा "किसी भी व्यक्ति" को संदर्भित करती है, इसमें वह व्यक्ति और तीसरा पक्ष दोनों शामिल हैं जिन्होंने विधेय अपराध किया है।

धुलाई करने वाले। हालांकि आम तौर पर राज्यों में सामान्य कानून परंपरा में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन यह सवाल हो सकता है कि क्या अपराध को उस व्यक्ति तक बढ़ाया जाना चाहिए जिसने भी विधेय अपराध किया है।

वियना और पालेर्मो समझौते एक अपवाद प्रदान करते हैं।

सामान्य सिद्धांत के लिए कि दोनों विधेय अपराधी और

तीसरे पक्ष को धन शोधन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए जहाँ

घरेलू कानून के मौलिक सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि यह उस व्यक्ति पर लागू न हो जिसने विधेय अपराध किया हो। कुछ देशों में, संवैधानिक सिद्धांत एक पर मुकदमा चलाने से रोकते हैं

धन शोधन और एक विधेय अपराध दोनों के लिए व्यक्ति। अधिकांश सामान्य कानून देशों के मामले में, ऐसे मौलिक सिद्धांत प्रतीत नहीं होते हैं जो इसके अनुप्रयोग को प्रतिबंधित करते हैं

स्व-शोधनकर्ताओं के लिए धनशोधन अपराध। हालांकि, अगर

एक अपवाद आवश्यक है, एक अतिरिक्त प्रावधान, क्योंकि धन शोधन का अपराध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो

यदि मसौदा तैयार करने वालों का मानना है कि "किसी भी व्यक्ति" के संदर्भ से परे अतिरिक्त स्पष्टता की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग अपनी आय का शोधन करते हैं, उन्हें कवर किया गया है, तो एक प्रावधान कर सकता है -

धारा 3 (2)-(5) में उल्लिखित अपराध उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे जिसने अपराध किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा अन्य अपराध (ओं), जिसने उत्पन्न किया

अपराध की आय "।

92. इसी तरह, मॉडल कानून में मसौदा नोट का हिस्सा, जिसमें ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो धन उगाही के अपराध का गठन कर सकती हैं, निम्नानुसार है:

" अपराधों के प्रकार: संयुक्त राष्ट्र के विधायी मार्गदर्शक के रूप में

पालेर्मो कन्वेंशन और विधायी गाइड

संयुक्त राष्ट्र संधि का कार्यान्वयन

भ्रष्टाचार स्पष्ट करता है कि वाई. बालाजी बनाम के चार सामान्य प्रकार हैं।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर., ई. टी. सी. [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

ऐसा आचरण जिसे अपराध घोषित किया जाना चाहिए। प्रत्येक के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं:

1. अपराध की आय का रूपांतरण या हस्तांतरण। इसमें ऐसे उदाहरण शामिल हैं जिनमें वित्तीय परिसंपत्तियों को एक रूप या प्रकार से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, उदाहरण के लिए, कीमती धातुओं या अचल संपत्ति की खरीद या अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अवैध रूप से उत्पन्न नकदी का उपयोग करके, साथ ही साथ ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं जिनमें समान परिसंपत्तियों को एक स्थान या अधिकार क्षेत्र से दूसरे स्थान पर या एक बैंक खाते से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है। ( उदाहरण के लिए, कार्यान्वयन के लिए विधायी मार्गदर्शिका में अनुच्छेद 232 देखें।

संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार संधि)। मानसिक के बारे में

तत्व, धर्मांतरण या हस्तांतरण जानबूझकर होना चाहिए, अभियुक्त को धर्मांतरण या हस्तांतरण के समय जानकारी होनी चाहिए कि संपत्ति आपराधिक आय है, और यह कार्य बताए गए दो उद्देश्यों में से किसी एक के लिए किया जाना चाहिए-आपराधिक मूल को छिपाना या छिपाना या किसी व्यक्ति की मदद करना।

2. अपराध की आय को छिपाना या छिपाना। प्रावधान में कई पहलुओं का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में छिपाया या प्रच्छन्न किया जा सकता है-लगभग कोई भी पहलू, या जानकारी। संपत्ति के बारे में, इसलिए यह खंड व्यापक है। छिपाना या छिपाना जानबूझकर होना चाहिए और अभियुक्त को यह जानकारी होनी चाहिए कि संपत्ति अधिनियम के समय अपराध की आय का गठन करती है। यह प्रावधान दूसरों के जानबूझकर धोखे से संबंधित है। इसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जानबूझकर धोखा देना शामिल होगा। असली प्रकृति अपराधी से प्राप्त होने का आवश्यक गुण हो सकता है।

गतिविधि। उत्पत्ति भौतिक उत्पत्ति या आपराधिकता में इसकी उत्पत्ति हो सकती है। इस दूसरे अपराध के लिए, इस बात के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि छिपाने या छिपाने का उद्देश्य संपत्ति का पता लगाने को विफल करना या इसकी वास्तविक उत्पत्ति को छिपाना है। हालांकि एक सामान्य मामले के रूप में यह छिपाने या प्रच्छन्न करने का उद्देश्य होगा, लागू संयुक्त राष्ट्र

सम्मेलनों के लिए आवश्यक है कि ऐसा अपराधीकरण हो जो इस तरह के उद्देश्य के प्रदर्शन पर निर्भर न हो।

3. आय का अधिग्रहण, कब्जा या उपयोग। यह खंड उन प्राप्तकर्ताओं पर दायित्व लगाता है जो [2023] 8 एस. सी. आर. प्राप्त करते हैं, रखते हैं या उपयोग करते हैं।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्ति, और उपरोक्त दो प्रावधानों के विपरीत है जो अवैध आय प्रदान करने वालों के लिए दायित्व से संबंधित है। अर्जित करने, रखने या उपयोग करने का इरादा होना चाहिए, और अभियुक्त को अधिग्रहण या प्राप्ति के समय ज्ञान होना चाहिए कि

संपत्ति आय थी।

4. इसमें भागीदारी, सहयोग या साजिश करना, प्रतिबद्ध होने और सहायता करने का प्रयास करना, बढ़ावा देना, सुविधा प्रदान करना और परामर्श देना। अपराध के शारीरिक कृत्य के अलावा संलिप्तता या भागीदारी के अलग-अलग स्तर हैं:

सहायता (सहायता और प्रोत्साहन, सुविधा प्रदान करना) और

प्रोत्साहन (परामर्श)। इसके अलावा, प्रयासों को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। अंत में, इस धारा में षड्यंत्र शामिल है, ए सामान्य कानून अवधारणा, या एक विकल्प के रूप में, का एक संघ

अपराध करने के लिए एक साथ काम करने वाले व्यक्ति।

ज्ञान: सुझाए गए रूप पहले हैं, ज्ञान का मूल है कि संपत्ति अपराध की आय है (जो

ज्ञान का अनुमान वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक से लगाया जा सकता है। परिस्थितियाँ); और दूसरी बात ज्ञान या संदेह का एक अधिक लचीला मानक कि संपत्ति की आय है

अपराध "।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि पीएमएलए के प्रावधान यू. एन. ओ. डी. सी. द्वारा तैयार किए गए आदर्श कानून के अनुरूप हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, आइए अब

इन दोनों प्रश्नों का उत्तर खोजें। प्रश्न 1: चाहे अपराध की आय की पहचान किए बिना या अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति और

धारा 3 द्वारा आवश्यक अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि की पहचान किए बिना, जो मूलभूत/क्षेत्राधिकार तथ्य, ईडी एक जांच शुरू कर सकता है और समन जारी कर सकता है?

93. अभियुक्त के लिए विद्वान वकील के गीत का सामान्य विषय यह है कि केवल एक विधेय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करना,

भले ही यह एक अनुसूचित अपराध हो, ईडी के लिए सूचना रिपोर्ट दर्ज करना और किसी को भी तलब करना पर्याप्त नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, अनुसूचित अपराध के होने से अपराध की आय उत्पन्न होनी चाहिए थी और अपराध की आय होनी चाहिए थी ईडी के दखल के लिए किसी ने कपड़े धोए। एक कदम आगे बढ़ते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि ईडी को पहले वाई. बालाजी बनाम की पहचान करनी चाहिए।



कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति, एक

मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है और धारा के तहत समन जारी किया जाता है।<sup>94</sup> इन विवादों को, हमारी राय में, यदि स्वीकार किया जाता है, तो घोड़े के सामने गाड़ी को मोड़ने के बराबर होगा। बदकिस्मती से अभियुक्त के लिए यह

अधिनियम की योजना।

95. अधिनियम की धारा 3 जो धन के अपराध को परिभाषित करती है

एरिंग इस प्रकार पढ़ता है:

" 3. धनशोधन का अपराध। जो भी सीधे या

अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने या जानबूझकर सहायता करने का प्रयास या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है। धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए, यह एतद्वारा है

स्पष्ट किया कि, ( i) एक व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन का प्रयास करते हुए पाया जाता है।

शामिल या जानबूझकर सहायता या जानबूझकर एक पार्टी है या वास्तव में है

निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रक्रियाओं या गतिविधियों में शामिल होना।

अपराध की आय से संबंधित, अर्थात्:

( (ख) स्वामित्व; या

( ग) अधिग्रहण; या

( (घ) उपयोग; या

( (ई) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या  
संपत्ति के रूप में दावा करना,

( च) बेदाग

किसी भी तरह से;

( (ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि।

यह एक निरंतर गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय का लाभ उठाते हुए

छिपाना या कब्जा या अधिग्रहण या उपयोग या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या इसे किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना।



हो। "[2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

96. यदि धारा 3 के मुख्य भाग को फॉरेंसिक सटीकता के साथ विच्छेदित किया जाता है,

यह स्पष्ट होगा कि धारा 3 तीन चीजों को संबोधित करती है (हम कर सकते हैं

उन्हें 3 'पी' कहें) अर्थात्, (i) व्यक्ति; (ii) प्रक्रिया या गतिविधि; और (iii) उत्पाद। जहाँ तक धारा 3 द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों का संबंध है, वे

(i) वे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करते हैं; या (ii) वे जो जानबूझकर सहायता करते हैं; या (iii) वे जो जानबूझकर एक पक्ष हैं; या (iv) वे जो वास्तव में शामिल हैं। जहाँ तक प्रक्रिया का संबंध है, धारा छह अलग-अलग गतिविधियों की पहचान करती है, अर्थात् (i) छिपाना; (ii) कब्जा; (iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) पेश करना; या (vi) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, जिनमें से कोई भी अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है।

जहाँ तक उत्पाद का संबंध है, धारा 3 "अपराध की आय" या प्रक्रिया या गतिविधि के उत्पाद के रूप में अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति की पहचान करती है।

97. उन तीन बातों में से जिन्हें धारा 3 संबोधित करती है, अर्थात् (i)

व्यक्ति; (ii) प्रक्रिया; और (iii) उत्पाद, पहले दो के लिए किसी व्याख्या या परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पहलू अर्थात् "उत्पाद", जिसे धारा 3 "अपराध की आय" के रूप में संदर्भित करती है, के लिए एक परिभाषा की आवश्यकता होती है और इसलिए इसे धारा 2 (1) (यू) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" 2. परिभाषाएँ। — ( 1 ) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकता है,

XXX

XXX

X

XX

अपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अनुसूचित अपराध या ऐसी किसी संपत्ति के मूल्य से संबंधित

या जहाँ ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली जाती है या रखी जाती है, तो

देश के भीतर या विदेश में आयोजित मूल्य में समतुल्य संपत्ति;

स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए, यह एतद्वारा है

अपराध; "

98. इन आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए जो बनाते हैं

धारा 3 की आणविक संरचना, यदि हम हाथ पर मामले पर वापस जाते हैं, तो हम

यह पाएगा कि (i) आई. पी. सी. की धारा 120बी, 419,420,467 और 471 के तहत अपराध अनुसूची के पैराग्राफ 1 में शामिल अनुसूचित अपराध हैं; वाई. बालाजी बनाम.

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

और (ii) कि पी. सी. अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत अपराध अनुसूची के पैराग्राफ 8 में शामिल हैं।

99. तीनों प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने अवैध रूप से रिश्वत लेकर अनुसूची में शामिल अपराध किए थे।

सार्वजनिक परिवहन निगम में कई व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करना। एक मामले में यह आरोप लगाया गया है कि 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि करोड़ एकत्र किए गए थे और एक अन्य मामले में Rs.95 लाख की राशि एकत्र की गई थी। यह रिश्वत की राशि है जो धारा 2 (1) (यू) के अर्थ के भीतर 'अपराध की आय' का गठन करती है। यह जानना कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है कि एक लोक सेवक अवैध रूप से संतुष्टि प्राप्त कर रहा है।

अपराध की आय का कब्जा। यह तर्क कि अपराध की आय का मात्र उत्पादन धन शोधन के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वास्तव में बेतुका है। जैसा कि हम धारा 3 से देख सकते हैं,

इसमें छह प्रक्रियाओं या गतिविधियों की पहचान की गई है। वे हैं, (i) छिपाना; (ii) अधिकार; (iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; और (vi) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना। अगर कोई व्यक्ति

रिश्वत लेता है, वह अपराध की आय प्राप्त करता है। इसलिए, "अधिग्रहण" की गतिविधि होती है। भले ही वह इसे अपने पास नहीं रखता है लेकिन इसका "उपयोग" करता है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि "उपयोग" धारा 3 में उल्लिखित छह गतिविधियों में से एक है।

100. विधेय अपराधों के लिए प्राथमिकियां धारा 3 के सभी तीन घटकों की पहचान करती हैं, अर्थात्, (i) व्यक्ति; (ii) प्रक्रिया; और (iii) उत्पाद। एफ. आई. आर. में अभियुक्त ओ लोक छथि जे एहिमे संलिस छथि।

प्रक्रिया या गतिविधि। अवैध संतुष्टि जो उन्होंने ली है,

अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करता है। (i) पहली बार में इस तरह की अवैध संतुष्टि का अधिग्रहण; (ii) इसे उपयोग में लाने से पहले दागी धन का कब्जा; और (iii) आज इसे बेदाग धन के रूप में पेश करना, वह प्रक्रिया या गतिविधि है जिसमें आरोपी शामिल हैं। द. भ्रष्टाचार का पैसा अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करता है।

101. इसलिए, सभी तर्क जैसे कि कोई मूलभूत तथ्य या क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य नहीं हैं, केवल धोखा देने के उद्देश्य से हैं।

अदालत। 102. यह सच है कि कुछ अपराध हैं, जो अनुसूचित अपराध होने के बावजूद, अपराध की आय उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, धारा 307 के तहत दंडनीय हत्या का अपराध एक अनुसूचित अपराध है। जब तक कि यह किसी भाड़े के हत्यारे द्वारा लाभ या हत्या के लिए हत्या नहीं है, तब तक वह आय उत्पन्न कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।

अपराध। इस प्रकार के अपराधों के संबंध में संभवतः [2023] 8 एस. सी. आर. हो सकता है।



### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह तर्क दिया जाता है कि केवल अपराध करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन अपराध की आय का सृजन आवश्यक है। भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन सियामी जुड़वा बच्चों की तरह होता है।

103. वास्तव में, पी. एम. एल. ए. धारा 2 (1) (वी) में "संपत्ति" शब्द को परिभाषित करता है।

इस प्रकार है:

" 2. परिभाषाएँ। — ( 1 ) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकता है, -

X

XX

XXX

XXX

( v ) "सम्पत्ति" से प्रत्येक विवरण की कोई सम्पत्ति या परिसंपत्ति अभिप्रेत है, चाहे भौतिक हो या अचल, चल या अचल, मूर्त

या अमूर्त और इसमें शीर्षक का प्रमाण देने वाले कार्य और उपकरण शामिल हैं।

ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियों में व्याज, जहां भी स्थित हो;

स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए, यह एतद्वारा है

स्पष्ट किया कि "संपत्ति" शब्द में किसी भी प्रकार की संपत्ति शामिल है।

इस अधिनियम या इनमें से किसी के तहत अपराध करने में उपयोग किया गया

अनुसूचित अपराध; "

104. इसलिए, भले ही एक अमूर्त संपत्ति एक परिणाम के रूप में प्राप्त की जाती है

किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि की, यह धारा 2 (1) (यू) के तहत अपराध की आय बन जाती है। उपरोक्त को देखते हुए, हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि ईडी द्वारा जांच बिना किसी मूलभूत/अधिकार क्षेत्र के तथ्यों के शुरू की गई थी। हमारे विचार में, एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप (i) आपराधिक गतिविधि में व्यक्तियों की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।

अनुसूचित अपराधों से संबंधित; (ii) धारा 3 के अर्थ के भीतर अपराध की आय का सृजन और (iii) धनशोधन। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि जहां भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वहां अपराध की आय का अधिग्रहण होता है जो अपने आप में धन शोधन के समान है।

#### 105. ईडी के पंजीकरण के बारे में बहुत गर्मी और धूल पैदा हुई थी

बिना किसी सामग्री के आई. डी. 1 पर सूचना रिपोर्ट और उसके बाद प्रत्यर्थियों को बुलाकर और विशेष न्यायालय से विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर मछली पकड़ने के अभियान में शामिल होना, जिसके समक्ष विधेय अपराधों से संबंधित शिकायतें लंबित हैं। लेकिन हम इन तर्कों में कोई सार नहीं देखते हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसका कारण समझ में आ जाएगा यदि हम कुछ तथ्यों पर वापस जाएँ।

वाई. बालाजी बनाम। कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

106. 29.10.2015 पर, देवासगयम ने शिकायत की। यह दस अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ था, लेकिन मंत्री, उनके भाई और उनके सचिव के खिलाफ नहीं था। लेकिन 07/08.03.2016 को, एक गोपी ने मंत्री के भाई का नाम लेते हुए शिकायत की और दावा किया कि कुल 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया था। इसके बाद गोपी ने उच्च न्यायालय की फाइल पर 2016 का आपराधिक ओ. पी. No.7503 दायर किया जिसमें उच्च न्यायालय ने जाँच का विस्तार करने और वास्तविक दोषियों के खिलाफ जाने के लिए 20.06.2016 पर एक आदेश पारित किया। लेकिन संहिता की धारा 173 (2) के तहत एक अंतिम रिपोर्ट 13.06.2017 पर दायर की गई थी। इसके बाद वी. गणेश कुमार द्वारा 2017 की एफ. आई. आर. No.298 में 09.09.2017 पर एक और शिकायत दर्ज की गई। इस एफ. आई. आर. में, 07.06.2018 पर एक अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसी तरह, एक अरुलमानी ने 2018 की एफ. आई. आर. No.344 में 13.08.2018 पर शिकायत दर्ज की जिसमें 12.04.2019 पर एक अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 107. इसके बाद, एक आर. बी. अरुण कुमार के कहने पर, 2015 की एफ. आई. आर. No.441 में आगे की जाँच का आदेश दिया गया।

उच्च न्यायालय दिनांकित 27.11.2019। इसके बाद, उन मामलों में से एक में मंत्री द्वारा आरोपमुक्त करने की याचिका दायर की गई और उसी के खारिज होने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। विचाराधीनता के दौरान

उनमें से एक में धारा 173 (8) के तहत एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी मामले।

सभी अवैध संतुष्टि सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई थी। कहने के लिए कि ईडी को शुतुरमुर्ग जैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, यह पता लगाने की कोशिश किए बिना कि घोटाले में उत्पन्न भारी धन कहाँ और किसके पास गया था, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में सुना नहीं गया है।

110. वास्तव में, ईडी किसी भी ऐसे दस्तावेज तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था जो पहुंच से बाहर था। उच्च न्यायालय के समक्ष कई कार्यवाहियों में, जैसे कि (i) आगे की जांच के लिए याचिकाएं; (ii) रिट याचिकाएं; और (iii) रद्द करने की याचिकाएं, कुछ दस्तावेज जिनकी प्रमाणित प्रतियां ईडी द्वारा मांगी गई थीं, पहले ही संलग्न किए जा चुके थे। ईडी केवल उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाहता था और इससे ज्यादा कुछ नहीं।

111. वास्तव में, एफ. आई. आर. के साथ-साथ अंतिम रिपोर्ट अब कुछ राज्यों में पुलिस विभाग की वेबसाइटों पर अपलोड की जाती हैं।

3] 8 एस. सी. आर. में

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने 2016 में ऑनलाइन एफ. आई. आर. अपलोड करना शुरू कर दिया था। सभी पुलिस स्टेशनों में एक अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसे 'सी. सी. टी. एन. एस.' के नाम से जाना जाता है। इसलिए,

एफ. आई. आर. से संबंधित जानकारी सार्वजनिक है।

112. एक बार जब सार्वजनिक रोजगार के मामले में भारी मात्रा में अवैध संतुष्टि के अधिग्रहण से संबंधित जानकारी सार्वजनिक हो जाती है, तो ईडी का कर्तव्य है कि वह एक सूचना रिपोर्ट दर्ज करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि "अधिग्रहण" एक गतिविधि है। धनशोधन की राशि और एक लोक सेवक द्वारा अर्जित अवैध संतुष्टि "अपराध की आय" का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक अनुसूचित अपराध के संबंध में आपराधिक गतिविधि के माध्यम से उत्पन्न होती है। इसलिए, इसके लिए किसी भी अभियान की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम मछली पकड़ने के अभियान की आवश्यकता है।

कोई यह कहने के लिए कि रिश्तों के पैसे की प्राप्ति धन शोधन का कार्य है।

113. श्री सिद्धार्थ लूथरा का तर्क कि ई. डी. की ओर से पंजीकरण में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था सूचना रिपोर्ट, एक स्व-सेवारत तर्क है। यदि ईडी प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है।

एक विशेष अपराध के लिए, ईडी पर जल्दबाजी में काम करने का आरोप लगाया जाएगा। यदि वे किसी विशेष चरण तक नाटक के सामने आने तक प्रतीक्षा करते हैं, तो ईडी पर देरी के दोषी के रूप में हमला किया जाएगा। 2016 से 2021 तक लंबा समय देने के लिए आरोपी को ईडी का शुक्रगुजार होना चाहिए।

114. इसलिए, तथ्यों पर सभी तर्क और विजय में फैसले के कुछ हिस्सों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी विवाद।

मदनलाल चौधरी, ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की वैधता को चुनौती देना पूरी तरह से अस्थिर है।

कुछ कार्यवाही में पारित किया गया है, यह इसके लिए आवश्यक है अदालत इन अपीलों को समीक्षा याचिका या स्थगन के साथ जोड़ती है

जब तक पुनरीक्षण याचिका और अन्य याचिकाओं में कोई निर्णय नहीं दिया जाता, तब तक इन मामलों की सुनवाई?

115. आइए अब विजय मदनलाल में निर्णय के कुछ हिस्सों की शुद्धता के इर्द-गिर्द घूमने वाले विवाद पर आते हैं।

चौधरी।

116. सबसे पहले, हमें यह इंगित करना चाहिए कि समीक्षा याचिका में आदेशित एक नोटिस समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) है। 2022 का <आईडी1, वाई. बालाजी बनाम नहीं होगा।

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

निर्दोषता का अनुमान। इस मामले में उत्तरदाता जिन बिंदुओं का प्रचार कर रहे हैं, उनका उन दो मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, अभियुक्त समीक्षा याचिका पर पिग्गीबैक सवारी नहीं कर सकता है।

117. वास्तव में, जैसा कि हमने कहीं और बताया है, अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कोई अपील नहीं की है

दिनांकित 01.09.2022। इसलिए, वे अधिकतम बहस करने के हकदार हैं।

केवल उक्त निर्णय के खिलाफ ईडी और अन्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज करने के लिए। मान लीजिए कि हम अभियुक्त के विद्वान वकील से सहमत हैं और ईडी द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हैं, तब भी उनके पास भागने का रास्ता नहीं हो सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश केवल तब तक उनकी रक्षा करता है जब तक कि अन्य कार्यवाही को रोक नहीं दिया जाता है।

118. इसलिए, अभियुक्त को न तो एक बड़ी पीठ के पास संदर्भ की मांग करने का अधिकार है और न ही निर्णय तक मामले को स्थगित करने का अधिकार है।

इसे बड़े मुद्दों से जुड़े मामलों में प्रस्तुत किया जाता है।

119. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश से उत्पन्न होने वाली अपीलों को अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार, इन अपीलों की अनुमति दी जाती है और डिवीजन बेंच का आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय दिनांकित 01.09.2022 को दरकिनार कर दिया गया है। ईडी अब उस चरण से आगे बढ़ने का हकदार होगा जिस पर उनके हाथ विवादित आदेश से बंधे थे।  
भाग-III (विशेष न्यायालय के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए ईडी को अनुमति)

120. पुनरावृत्ति करने के लिए, ईडी ने 29.07.2021 पर एक सूचना रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर प्राथमिकी की प्रमाणित प्रतियां, गवाहों के बयान आदि की मांग की। दिनांक 09.11.2021 के एक आदेश द्वारा, विशेष न्यायालय ने आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी और प्राथमिकी, शिकायत, बयानों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने का निर्देश दिया।

आदि, लेकिन अचिह्नित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने से इनकार कर दिया।

23 ] 8 एस सी आर।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

121. उक्त आदेश के खिलाफ ईडी ने संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया। इन याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी

उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.03.2022 के एक आदेश द्वारा, ईडी को नियम, 2019 के नियम 237 के तहत दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उसके बाद, एक नए तीसरे पक्ष की प्रति आवेदन दायर करने की अनुमति दी। यह इस आदेश के खिलाफ है कि 2021 के सीसी No.24 में संहिता की धारा 173 (8) के तहत दायर अंतिम रिपोर्ट में एम. कार्तिकेयन (अभियुक्त संख्या 3) नाम के अभियुक्तों में से एक ने एक अपील दायर की है।

122. इस अपील में अपीलार्थी की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय ने नियम, 2019 के नियम 211 (3) के प्रावधानों की अनदेखी की है।

और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 187235 की धारा 65 बी भी। लेकिन उपरोक्त दोनों तर्क आधारहीन हैं। नियम 211 मुख्य रूप से अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले अभियुक्त को कुछ अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के अनुदान से संबंधित है। नियम 211 (3) में कहा गया है कि अचिह्नित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नहीं दी जाएंगी। उच्च न्यायालय ने नहीं किया अचिह्नित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के अनुदान का निर्देश देने वाला कोई भी आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने केवल इतना किया है कि ईडी को नियम 237 के तहत दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उसके बाद एक उचित प्रति आवेदन दायर करने की अनुमति दी गई है। यह नियम 239 (3) के विपरीत नहीं है।

123. हम नहीं जानते कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के इर्द-गिर्द एक तर्क कैसे उठाया जाता है। धारा 65 बी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता से संबंधित है। प्रमाणन के बिना, ईडी पीएमएलए के तहत अभियोजन में सबूत में उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी नहीं देख सकते हैं।

124. इसलिए, हम अपील में कोई गुण नहीं पाते हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.03.2022 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील में पारित किया गया 2022 का आपराधिक ओ. पी. No.5726 खारिज कर दिया गया है।

#### भाग-IV (आगे पूरा करने के लिए समय का विस्तार)

जाँच) 125. वाई. बालाजी द्वारा दायर एक अपील है, जिसकी स्थिति हमारे द्वारा कहीं और एक सारणीबद्ध कॉलम में इंगित की गई है। उनकी अपील एक आदेश को चुनौती देती है

उच्च न्यायालय द्वारा मूल रूप से 27.11.2019 पर पारित अभियोजन पक्ष को 2017 के CC No.3627 में छह के भीतर आगे की जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया महीनों तक। जब समय बढ़ाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, तो अदालत ने इसे 01.11.2021 दिनांकित आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थना

35 संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम" वाई. बालाजी बनाम।



कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

निष्फल हो गया था। इसलिए, आगे की जांच के भाग्य के बारे में चिंतित, पीड़ित उपरोक्त अपील के साथ आया है। लेकिन अपीलार्थी की चिंता निराधार है। केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय ने समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आगे की जांच करने का निर्देश निष्फल हो गया है। इसके विपरीत, 2017 के CC No.3627 में 08.03.2021 पर संहिता की धारा 173 (8) के तहत एक अंतिम रिपोर्ट पहले ही दायर की जा चुकी है और अब यह 2021 का CC No.24 बन गई है।

126. इसलिए, 27.11.2019 और 01.11.2021 दिनांकित आदेशों को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी जाती है।

अवमानना याचिकाएँ

127. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाली याचिकाएं दायर की हैं जो जांच के प्रभारी हैं, इस आधार पर कि (i) पीसी अधिनियम के तहत अपराधों को 2021 के सीसी No.25 में शामिल नहीं किया गया है; (ii) दो आपराधिक मामलों में अंतरिम रोक को खाली करने के लिए कदम नहीं उठाए गए थे; और (iii) कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक भ्रामक तस्वीर पेश की गई थी जैसे कि जांच अधूरी थी।

128. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार और राज्य की ओर से ए. ए. जी. श्री तिवारी ने कहा कि

129. वर्तमान में, हम कथित अवमानकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करेंगे। यही कारण है कि कथित हम जहां हैं, उसके लिए अकेले अवमानकों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। पूरा मामला एक मैच निकला जहां यह पहचानना असंभव हो गया कि कौन किस टीम के लिए खेल रहा था। इस अदालत के दिनांकित आदेश के बावजूद

08.09.2022 , उच्च न्यायालय ने दिनांकित 31.10.2022 आदेश पारित किया, जो व्यावहारिक रूप से इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को समाप्त करने का प्रभाव रखता है। अपने दिनांकित 31.10.2022 आदेश में, उच्च न्यायालय ने विभिन्न स्थानों पर हमारे आदेश का उल्लेख किया और अंततः इस न्यायालय के आदेश के प्रभाव को नष्ट कर दिया। इसलिए अकेले पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

23 ] 8 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, यदि भविष्य की जाँच इस न्यायालय के आदेशों की कोई अवज्ञा दिखाती है, तो यह याचिकाकर्ता के लिए हमेशा खुला रहेगा:

फिर से ऊपर आओ। इस अवलोकन के साथ, अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

### I.A.No। 2023 का 26257

बाद की घटनाओं से गलत साबित हुआ। इसलिए, आवेदक प्रार्थना करता है कि अब विशेष जांच दल के गठन का समय आ गया है। 131. आवेदन का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि (i) इस प्रकृति की प्रार्थना एक अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से नहीं की जा सकती है; और

( (ख) अभियोजन पक्ष के मंत्री द्वारा प्रभावित होने के आरोप की पुष्टि नहीं होती है।

132. जैसा कि हमने अवमानना से निपटने के दौरान बताया है

याचिकाओं में, इस विफलता के लिए पूरा दोष अकेले पुलिस के दरवाजे पर नहीं डाला जा सकता है। हम कई सह-भागीदार पाते हैं। इसलिए हम अस्वीकार करते हैं।

यह आई. ए. इस स्तर पर आवेदक को स्वतंत्रता के साथ एक महत्वपूर्ण याचिका के साथ वापस आने की स्वतंत्रता देता है, जिसमें इस तरह की प्रार्थना की मांग की जाती है, बाद में, जब किसी गड़बड़ी का संदेह हो। तदनुसार, 2023 का आई. ए. No.26257 उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया है।

### नतीजों का सारांश

133. पूरी चर्चा का सारांश इस प्रकार है:

( i) नए सिरे से जाँच के आदेश से उत्पन्न होने वाली अपीलों की अनुमति है। 2021 के आपराधिक ओ. पी. संख्या 15122 में पारित उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.10.2022 के आदेश के उस हिस्से को दरकिनार कर दिया गया है। नई जांच के लिए उक्त मूल याचिका में जारी किए गए निर्देशों को दरकिनार कर दिया गया है। जांच अधिकारी सभी मामलों में आगे की जांच के साथ आगे बढ़ेगा। पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करके मामले। इस संबंध में जांच अधिकारी की ओर से कोई भी छूट इसके लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

अदालत भविष्य में एक विशेष जांच दल नियुक्त करने पर विचार करेगी।

( (ii) डिवीजन बेंच के आदेश से उत्पन्न अपीलें

उच्च न्यायालय दिनांकित 01.09.2022 की अनुमति है। आदेश दिनांक 01.09.2022 Y. बालाजी v.

कार्तिक देसाई और ए. एन. आर. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

एक तरफ़ की शुरुआत को चुनौती देने वाली तीनों रिट याचिकाएँ  
ईडी द्वारा किए गए संशोधन खारिज कर दिए जाएंगे।

( iii) उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश से उत्पन्न अपील

. 2022 बर्खास्त किया जाता है।

( iv) दिनांकित 27.11.2019 आदेशों को चुनौती देने वाली अपील और

. 2021 पूरा करने के लिए समय बढ़ाने से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया जाता है।  
जाँच अधिकारी आगे की जाँच जारी रखेगा और दो के भीतर आगे/अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेगा।

एच. एस.

( v) अवमानना याचिकाएँ और 2023 की आई. ए. संख्या 26257 हैं -

एसएसईडी।

अभियोग दाखिल करने का आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

अपीलों का

निपटारा किया गया।

पांडे

शेवाली मोंगा, एल. सी. आर. ए.)